₹ 10

www.kewalsachtimes.com

मार्च 2022

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BHIBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PT-78

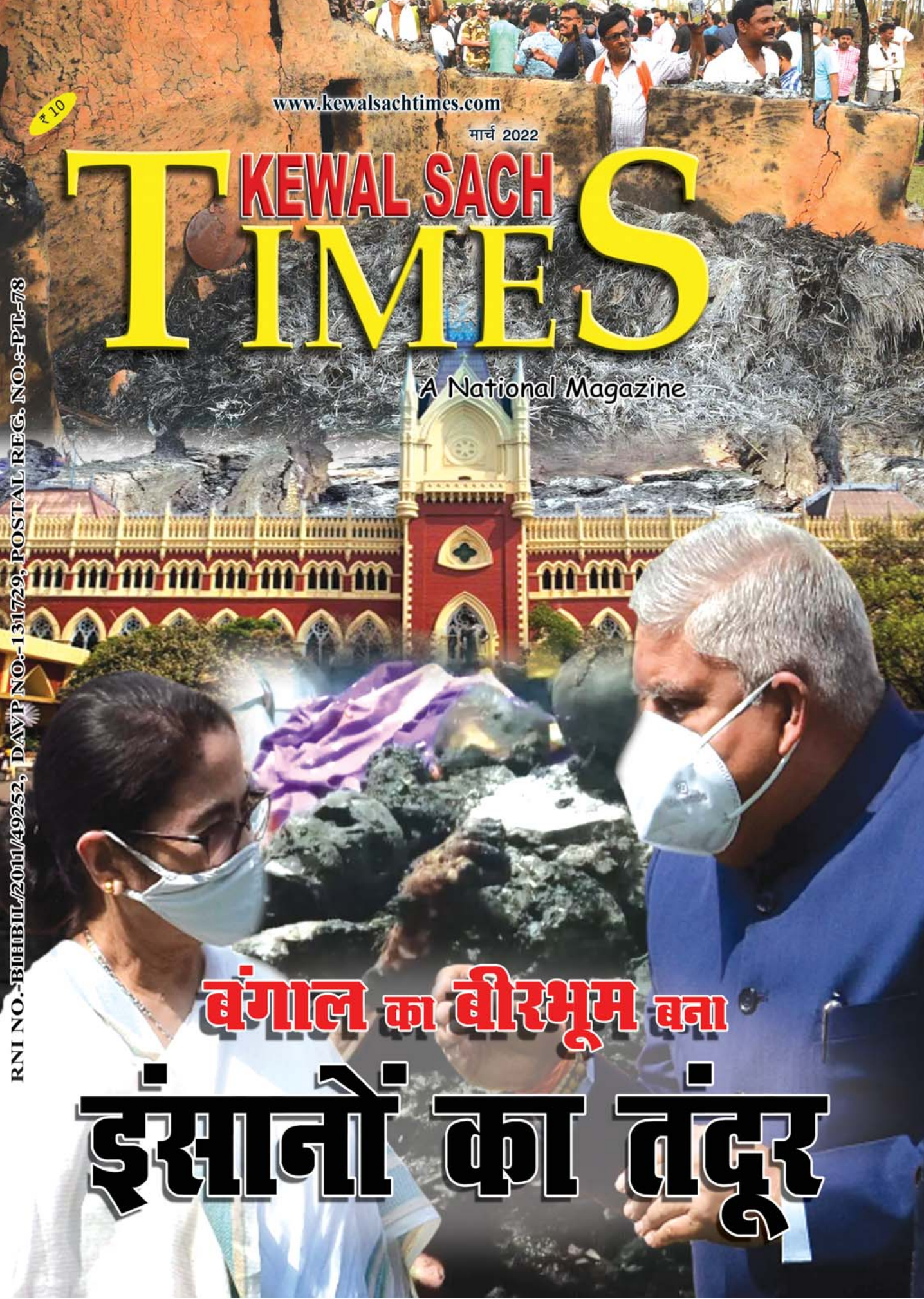

बंगाल का बीरभूम बना

इंसानों का तंदूर

जन-जन की आवाज है केवल सच

निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
www.kewalsach.com
Kewalsach news
Mob.: 9431073769, 9308815605
खबर वहीं,
जो केवल सच हो

केवल सच TIMES
21 तक आने की संभावना नहीं: विज्ञान मंत्रालय

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM | UPI
G Pay पे Paytm

www.kewalsach.com
www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

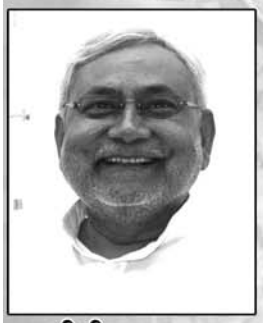

नीतीश कुमार
01 मार्च 1951

मेरी कॉम
01 मार्च 1983

शंकर महादेवन
03 मार्च 1967

शिवराज सिंह चौहान
05 मार्च 1959

अनुपम खेर
07 मार्च 1955

नवीन जिंदल
09 मार्च 1970

उमर अब्दुल्लाह
10 मार्च 1970

श्रेया घोषाल
12 मार्च 1984

वरूण गांधी
13 मार्च 1980

अमीर खान
14 मार्च 1965

हनी सिंह
15 मार्च 1984

राजपाल यादव
16 मार्च 1971

सानिया नेहवाल
17 मार्च 1990

रानी मुखर्जी
21 मार्च 1978

स्मृति जुबैद ईरानी
23 मार्च 1976

इमरान हाशमी
24 मार्च 1979

मधु
26 मार्च 1972

प्रकाश राज
26 मार्च 1965

शीला दीक्षित
31 मार्च 1938

मीरा कुमार
31 मार्च 1945

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi-834001 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:-
editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
	Cover Page	3,00,000/-	N/A
	Back Page	1,00,000/-	65,000/-
	Back Inside	90,000/-	50,000/-
	Back Inner	80,000/-	50,000/-
	Middle	1,40,000/-	N/A
	Front Inside	90,000/-	50,000/-
	Front Inner	80,000/-	50,000/-

B & W	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
	Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

आउटसोर्सिंग के नाम पर भ्रष्टाचार

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

Government Job के बजाय Outsource पर Job की प्रथा पूरे देश में बड़ी तेजी से अपना पांव पसार रही है ताकि सरकार को कम राशि पर श्रमिक एवं पदाधिकारी मिल जाते हैं और कंपनी को इसके एवज में मोटी कमीशन मिल जाती है और Outsource पर कार्य निर्गत करने वाले विभाग के बाबू से लेकर विभागाध्यक्ष तक हिस्सा बंटता है परन्तु दूसरा पहलू यह भी है आउटसोर्सिंग के नाम पर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। मोदी की सरकार हो या नीतीश कुमार की या फिर अन्य राज्य की सरकारें सभी जगहों पर सरकारी नौकरी की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास चल रहा है लेकिन इन्हीं कारणों की वजहों से सरकार की गोपनियता भंग भी हो रही है क्योंकि संविदा पर कार्य करने वाली कंपनी का टर्म पूरा होने के बाद कोई जरूरी नहीं है की उसी कंपनी को दोबारा काम मिल जाये इसलिए संविदा पर कार्य कर रही कंपनी के Worker भी कम वेतन मिलने के बाद भी हंगामा नहीं करते जबकि उनका PF और ESIC पर भी कंपनी भ्रष्टाचार करती है। पटना उच्च न्यायालय एवं श्रमायुक्त कार्यालय ने कई कंपनी को PF जमा नहीं करने की वजह से फटककार भी लगायी है और फाइन भी किया है। विभाग हो या मंत्रालय कम्प्यूटर से लेकर साफ-सफाई, सुरक्षा, वाहन सहित विभिन्न प्रकार की सप्लाई और तो और अधिकारी एवं कर्मचारी तक आउटसोर्स पर इस्तेमाल किये जा रहे हैं और यही कारण है कि विभाग एवं मंत्रालय में भ्रष्टाचार दीमक की तरह प्रवेश कर चुका है और धीरे - धीरे स्थिति भयावह होती जा रही है और असंतोष का माहौल बनता जा रहा है। सरकार भ्रष्टाचार से निवारण के लिए बातें तो बड़ी-बड़ी करती है पर सच्चाई यही है की भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगने की वजह से सरकारी खजाने का 50 प्रतिशत राशि भ्रष्टाचारियों के हत्थे चढ़ जाता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ईडी , आयकर, सीबीआई तो राज्य में निगरानी एवं आर्थिक अपराध शाखा काम कर रही है और तो और सभी विभाग का खुद का विजलेंश अलग होता है, बावजूद इसके आजादी के 75 वर्ष बाद भी हिन्दुस्तान को भ्रष्टाचारियों के आतंक से मुकत नहीं करा सके। सीबीआई हो या निगरानी विभाग पदाधिकारी एवं कर्मचारी को 2- 5 हजार हजार रूपये लेते हुए भी रंगे हांथ पकड़ती है और 1-2 लाख लेते हुए भी परन्तु केन्द्र सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारी को राज्य सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारी से ज्यादा दंड भुगतना पड़ता है। रंगे हाथ पकड़े गये पदाधिकारी या कर्मचारी कुछेक महीने या वर्षो बाद छूट जाते हैं और उसी विभाग में बहाल होकर फिर से सेवा देने लगते हैं वैसे में भ्रष्टाचार करने वाले निडर होते जा रहे हैं कि उनकी कमाई का कुछ हिस्सा में से बंटवारा करना पड़ा। वैसे में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कैसे संभव है और उससे भी हास्यास्पद बात तो यह है कि अगर कोई रंगे हांथ पकड़ा गया तो छूटा कैसे और छोड़ना हीं था तो रंगे हाथ पकड़ा ही कैसे? यह अहम सवाल है और इन्हीं कारणों की वजह से बैंक में होने वाली डकैतियों में भ्रष्टाचार किया गया रूपया को जोड़ दिया जाता है ताकि घोटाले की राशि भी डकैतों के मत्थे मढ़ दिया जाये। भ्रष्टाचार से कोई विभाग अछूता नहीं है और ना ही कोई प्रोडक्ट इसका उदाहरण चारा से लेकर टैंक तक में भ्रष्टाचार हुए हैं और अब नये दौर में तो सरकार भी यह स्वीकार कर चुकी है कि विकास की तेज रफ्तार में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने वेतन एवं सरकार से मिलने वाले सभी सुविधाओं के जोड़ने के बाद भी उनकी 100 प्रतिशत संपत्ति कैसे 1000 गुणा बढ़ जाती है। यह सरकार को नहीं मालूम? क्या बात न्यायालय को नहीं मालूम? क्या यह बात income जंग को नहीं मालूम? क्या यह E. D. को नहीं मालूम? क्या यह बात राजनेताओं को नहीं मालूम की सेवा में आने के वक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी की औकात क्या थी और शपथ लेकर सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि का पद पर बहाल नेता जी के पास यह अकूत संपत्ति हासिल हुई है? देश की आवाम को धर्म, जात-पात, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के विषय में फंसकर पिस रही है और इसी का लाभ लोकतंत्र के स्तंभकार बहुत मजबूती से कानून का पालन करते हुए अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। विदेशों से आ गया काला धन? नोटबंदी से आ गया कालाधन? निगरानी एवं सीबाई की जांच से आ गया कालाधन? अब तो सारे काम Outsource के माध्यम से हो रहा है और बात बिगड़ता देख तात्ककालीन सरकार उस कंपनी का संविदा रद्द करके खुद को पाक-साफ साबित करती है लेकिन उसके Outsource के कारण हुए भ्रष्टाचार पर निगरानी कैसे संभव है। 10 का 100 में होगा तो स्वाभाविक है इसमें सरकार एवं उसके पदाधिकारी का मिलीभगत होगा अन्यथा 02 साल का काम 05 में होगा तो एस्टिमेट घोटाला का होना स्वाभाविक है। जनता के आंख में धूल झोकने के लिए कई उदाहरण है और नोटबंदी के समय जब देश का अर्थ-व्यवस्था चौपट थी तो जय शाह की कंपनी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से मुनाफा कमा रहे थे परन्तु विपक्षियों की बात को जनता ने एक सिरे खारिज कर दिया। Outsource पर Job तो ही अब कंपनी को प्राईवेट ही किया जा रहा है ताकि Outsource से हो रही भ्रष्टाचार की बदनामी को ही खत्म कर दिया जाये। कैंसर जैसी बीमारी से एक मरीज और उसका परिवार का पतन हो जाता है परन्तु भ्रष्टाचर की बलिवेदी पर चढ़ने से प्रदेश - देश का ही सत्यानाश तय है।

देश में बेरोजगारी, महंगाई की समस्या से भी बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है और इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी है की सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, खासकर राज्य की सरकारों में यह अपना पांव बहुत तेजी से पसारता जा रहा है। एक तरफ जनसंख्या अनियंत्रित होती जा रही है वैसे में बेरोजगारी को कंट्रोल करना आसान नहीं है और सरकार पर बोझ अधिक नहीं हो इस वजह से आउटसोर्स पर काम लिया जा रहा है लेकिन इस आउटसोर्सिंग के कार्य के आवंटन से लेकर उसके भुगतान में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है तो दूसरी तरफ सरकार के कंधे पर पदाधिकारी से मिलीभगत करके कंपनियां भारत सरकार के श्रम कानून एवं नियमों का खुल्लेआम उल्लंघन कर रही है और करोड़ों रूपये सरकार से डकार रही है और श्रमिकों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। एक तरफ आउटसोर्स पर विकास करने का दावा करने वाली सरकार का खजाना और प्रतिष्ठा दोनों को लूटा जा रहा है और इस खेल में पदाधिकारियों की भूमिका काफी संदिग्ध है। श्रमिकों का शोषण पहले कल-कारखाने में किया जाता था की बातें सार्वजनिक होती थी और वह श्रमिक श्रम आयुक्त के यहां न्याय की गुहार लगाते थे और आज तो सरकार ने जिस कंपनी को कार्य दिया है वहीं श्रमिकों का खुल्लेआम शोषण कर रही है सरकार की जानकारी में, वैसे में श्रमिकों की रक्षा के लिए सिर्फ न्यायालय ही एक मात्र स्थल बचा है वैसे में आउटसोर्सिंग का कार्य कर रहीं कंपनियों पर कैसे नकेल कसा जायेगा यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है। बिहार में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाली कंपनी के चंगुल में बिहार सरकार का कई विभाग हैं जिससे मुक्ति दिलाना सरकार के लिए ही बड़ी चुनौती बन चुकी है जिससे श्रमिकों को न्याय दिलाना कठिन है।

KEWAL SACH TIMES
A National Magazine
वर्षः- 11, अंकः- 129 माहः- मार्च 2022 रू. 10/-

Editor in chief
Brajesh Mishra 09431073769
09955077308
08340360961
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

General Manager (H.R)
Triloki Nath Prasad 09308815605, 09122003000

General Manager (Advertisement)
Manish Kamaliya 6202340243
Reeta Singh 9308729879
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor
Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor
Amitabh Ranjan Mishra 08873004350
S. N. Giri 09308454485

Asst. Editor
Sashi Ranjan Singh 09431253179
Rajeev Kumar Shukla 07488290565

Sub. Editor
Brajesh Sahay 07488696914

Bureau Chief
Sanket kumar Jha 07762089203

Bureau
Sridhar Pandey 09852168763

Photographer
Mukesh Kumar 0 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड
संजय कुमार सिन्हा 09868700991

झारखण्ड हेड
ब्रजेश मिश्र (2) 07979769647
07654122344

पश्चिम बंगाल हेड
अजीत दुबे 09433567880
09339740757

मध्यप्रदेश हेड
अभिषेक पाठक 08109932505, 08269322711

छत्तीसगढ़ हेड
डिगल सिंह 09691153103
08982051378

उत्तर प्रदेश हेड
निर्भय कुमार मिश्रा 09452127278

उत्तराखण्ड हेड
आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड
कमोद कुमार कंचन 07492868363

गुजरात हेड
आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड
श्रवण कुमार चंचल 08977442750

राजस्थान हेड
आवश्यकता है

पंजाब हेड
आवश्यकता है

राजस्थान हेड
आवश्यकता है

उड़ीसा हेड
आवश्यकता है

आसाम हेड
आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय
केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
97 ए, डी डी ए फ्लैट
गुलाबी बाग, नई दिल्ली- 110007
मो०- 09868700991, 09431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय
केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 09433567880, 09339740757

झारखण्ड कार्यालय
केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
रिया प्लाजा, तीसरा तल्ला, कोकर चौक,
राँची (झारखण्ड)
मो०- 9955077308, 9431073769

महाराष्ट्र कार्यालय
केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- कमोद कुमार कंचन
Swapnapoorti Society,
Phase- 1, Sector - 26,
Nigdi, Pune- 411044
Mob:- 07492868363

छत्तीसगढ़ कार्यालय
केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- नूर आलम
हाउस नं.-74, अटल आवास, बेलभाँटा,
अभनपुर, रायपुर (छत्तीसगढ़)
मो०- 09835845781, 08602674503

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,
मकान संख्या- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

फरवरी 2022

अमृत काल

मिश्रा जी,

हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, महंगाई, गरीबी और महालूट के दौर में आपका आलेख सरकार को आइना दिखा रहा है। केवल सच टाइम्स का फरवरी 2022 अंक का संपादकीय 'तनाव एवं समस्या के बीच अमृत काल' में आमजनता के जीवन की सच्चाई को प्रकाशित कर दिया गया है। राजनीति की बलिवेदी पर चढ़ रही जनता का सुनने वाला कोई नहीं दिखता और जिस जनता से पगार ले रहे जनप्रतिनिधि एवं कार्यपालिका और न्यायपालिका उससे सीधे मुँह बात तक नहीं करती। तानाशाही और भ्रष्टाचार के बीच व्यवस्था चल रहा है और दबंगो की समाज में पूछ है।

● **मनीष पाठक, चितरंजन कारखाना, पं. बंगाल**

सियासत

संपादक महोदय,

भारत देश के पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर ऋतुपर्ण ववे ने फरवरी 2022 के केवल सच टाइम्स में बहुत ही दमदार खबर लिखी है। ''क्या सियासत की नई इबारत लिखेंगे यह पांच राज्य?'' खबर में राजनीतिक दलों के सूझबूझ एवं कूटनीति को बारीकी से लिखा गया है तथा एक तरह से यह इशारा भी किया गया है कि चुनाव के परिणाम क्या होंगे। जिस प्रकार चुनाव के दरम्यान कोरोना महामारी और हिजाब के साथ साथ बाबा का बुलडोजर पर चर्चा होता रहा वहीं अखिलेश की कूटनीति काम नहीं आ रही है। केवल सच टाइम्स के फरवरी अंक में एक से बढ़कर एक खबर है।

● **प्रमोद जाटव, नोयडा सेक्टर-16, यूपी**

बम ब्लास्ट

संपादक महोदय,

28 जुलाई 2008 अहमदाबाद शहर में 22 जगहों पर बम विस्फोट की धमाकों की गूंज आज भी सुनाई देती है लेकिन असत्य का सर्वनाश सुनिश्चित है। केवल सच टाइम्स में 'अहमदाबाद बम ब्लास्ट दोषियों को फांसी मुकर्रर' मुख्य खबर में पत्रकार अमित कुमार ने बहुत ही सटीक जानकारी के साथ विभिन्न पहलुओं की सार्थक समीक्षा की है। फरवरी 2022 अंक का यह खबर वास्तव में संग्रहणीय है। देश मे यह पहली बार हुआ है कि एक ही मामले में 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। आज भी एक ग्रुप को यह फैसला उचित नहीं लग रहा है। मजबूत एवं सटीक खबर।

● **कौशल उरांव, कांटाटोली चौक, राँची**

नीरा

संपादक महोदय,

बिहार में शराबबंदी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नीरा का सेवन का सलाह देना लाभकारी है सरकार के लिए भी और इसका इस्तेमाल करने वालों का भी। फरवरी 2022 अंक में ललन कुमार प्रसाद की खबर 'नीरा पौष्टिक प्राकृतिक पेय भी, गुणकारी औषधि भी' में काफी जानकारीप्रद बातों को रखा गया है। नीरा को ताड़ी भी कहा जाता है जिसे दोपहर में पीने के बाद नशीला प्रदार्थ बन जाता है, जो बिहार में बंद है। काफी रोचक तथ्यों के साथ यह खबर लिखा गया है कि नीरा और ताड़ी में क्या अंतर है तथा कानून बनाकर नीरा पीने के लिए प्रेरित करे सरकार पर भी प्रकाश डाला गया है।

● **मनोज पासवान, टावर चौक, मुंगेर**

एक पर एक

मिश्रा जी,

फरवरी 2022 अंक में हिजाब की खबर को पढ़ा तो ऐसा लगा की पत्रकार ने वास्तविक स्थिति को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। हिजाब एक बहाना है यह तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के गद्दी पर नहीं आने देने के लिए अभियान है। हिजाब ने इस मुद्दे को जय श्री राम बनाम अल्लाह हू अकबर बना दिया। धर्म की राजनीति के मामले में स्पष्ट हो जाता है कि देश के प्रति कितने वफादार हैं यह राजनेता । अल्लाह की लड़कियां हिजाब तो जय श्रीराम की लड़कियां भगवा दुपट्टा को लेकर मैदान में हैं।

● **कन्हैया शर्मा, साकेत बिहार, नई दिल्ली**

नक्शे कदम पर शिवराज

ब्रजेश जी,

मैं केवल सच टाइम्स का नियमित पाठक हूं और सभी खबरों को पढ़ता हूँ विशेषकर संपादकीय। फरवरी 2022 अंक में पत्रकार अरबिंद तिवारी की खबर 'मोदी के नक्शेकदम पर शिवराज' में मध्यप्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर खबर बनाई है कि जिस प्रकार पीएम मोदी जिस जगह जाते हैं वही के वेशभूषा पहनते हैं और वहीं की भाषा भी बोलते हैं, उसी प्रकार शिवराज चौहान को उनके नक्शेकदम कहें या नकल कर रहे हैं। राजनीति से ओतप्रोत लगी यह खबर जिसमे शिवराज चौहान को पीएम मटेरियल बताया जा रहा है जबकि यूपी में योगी भी पीएम मोदी के बाद प्रबल दावेदार हैं।

● **पंकज पटेल, रेलवे क्वाटर, भोपाल**

अन्दर के पन्नों में

17

19

28

40

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

देवब्रत्त कुमार गणेश

मुख्य संरक्षक सह भावी प्रत्याशी, 53 ठाकुरगंज विधानसभा
" **केवल सच** " पत्रिका **एवं** " **केवल सच टाइम्स** "
8986196502/9304877184
devbartkumar15@gmail.com

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक "**मगध इंटरनेशनल स्कूल**" टेकारी
" **केवल सच** " पत्रिका **एवं** " **केवल सच टाइम्स** "
9060148110
sudhir4s14@gmail.com

पत्रिका संरक्षक

श्री जय कुमार सिंह	:- मंत्री, आई. टी. विभाग, बिहार सरकार	9431821104
डॉ० उमाकान्त पाठक	:- जेनरल फिजिशियन, MBBS	9835291966
भगवान सिंह कुशवाहा	:- पूर्व मंत्री, बिहार सरकार	9431821525
श्री ललन पासवान	:- विधायक, चेनारी, रालोसपा	9431483540
डॉ० ए० के० सिंह	:- शिशु रोग विशेषज्ञ MBBS	9431258927
श्रीमती अरूणा सिंह	:- सदस्य, जिला पार्षद, बिक्रमगंज	9931610437

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C
08877663300

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

एक नजर

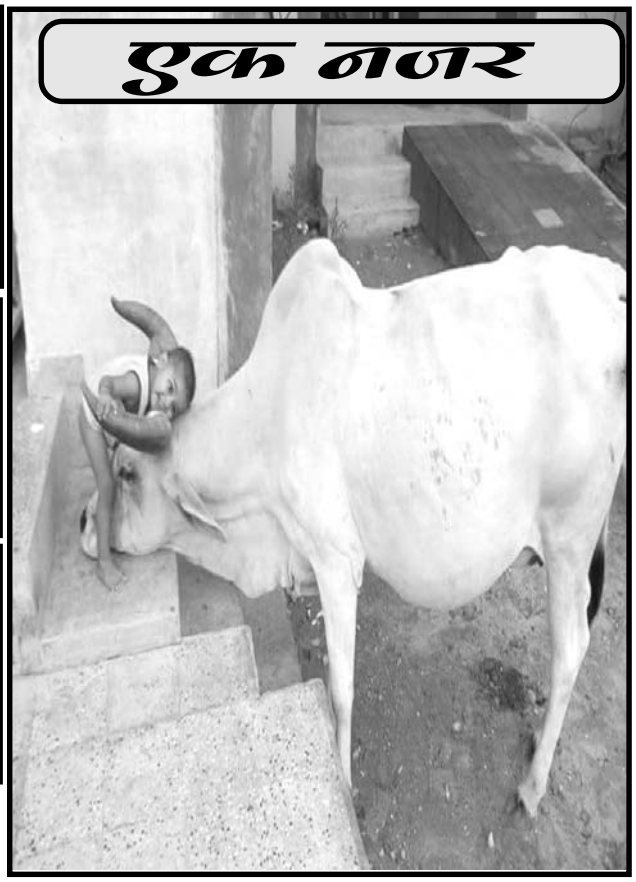

संपादकीय व प्रधान कार्यालयः-

☛ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्याः- 28/14, कंकड़बाग,पटना-800020(बिहार)
e-mail:- kewalsach@gmail.com,
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☛ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**

☛ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
☛ सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
☛ आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
☛ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
☛ सभी पद अवैतनिक हैं।
☛ विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
☛ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
☛ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
☛ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
☛ भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।
☛ A/C No. :- 20001817444
BANK :- State Bank Of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of "APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

Registered Under the Indian Society Act 21, 1880

East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020

Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077

E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com

Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

APNA GHAR

Now in the State of Bihar & Jharkhand

Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence in the lives of many Sr. Citizens.

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

A/C No.	-	**0600010202404**
Bank Name	-	**United Bank of India**
IFSC Code	-	**UTBIOKKB463**
Pan No.	-	**AAAAK9339D**

बंगाल का बीरभूम बना इंसानों का तंदूर

● अमित कुमार

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में 7 लोगों की जलकर मौत हो गई। खबरों के मुताबिक इन सभी को जलाकर मारा गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या का बदला लेने के लिए इन सभी लोगों को आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। मामला बीरभूम जिले के रामपुरहाट का है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जहां घरों के दरवाजे बंद कर आग लगा दी गई। इसमें मौके पर लोगों की जलकर मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार, ये वारदात टीएमसी के उपप्रधान की हत्या का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। गौरतलब हो कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा पर सियासी संग्राम छिड़ गया। वहीं घटनास्थल पर जा रहे बीजेपी

के प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने से रोका गया। आखिर बीरभूम में हिंसा की आग क्यों फैली, जानिए पूरा घटनाक्रम।

बताते चले कि रामपुर हाट में टीएमसी पंचायत नेता भादू शेख की हत्या कर दी गई थी। खबरों के मुताबिक उन पर बम फेंका गया था। बताया गया कि इसके बाद गुस्साई भीड़ ने लोगों के एक दर्जन से ज्यादा घरों में आग लगा दी। इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस ने इन संदिग्ध लोगों के नाम का खुलासा नहीं किया। वही इस हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को 24 मार्च को केस डायरी लाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य सरकार को भी निर्देश दिए गए कि वह गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराये। इसके अतिरिक्त जहां इस हिंसा को

अंजाम दिया गया, वहां किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं करने के निर्देश भी जारी किए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि इसके लिए उस जगह पर कैमरे लगाए जाएं। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी दल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वही विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था तेजी से चरमरा गई है। पंचायत उपप्रधान (उप प्रमुख) की हत्या के बाद बीरभूम जिले के रामपुरहाट इलाके में तनाव और दहशत फैल

गई है। भादू शेख कथित तौर पर एक बम हमले में मारा गया था। गुस्साई भीड़ ने बाद में तोड़फोड़ की और कई घरों में आग लगा दी। बता दें कि बीरभूम की घटना पर बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। वही बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि 2 दिन में 13 लोगों की हत्या हुई। कई लोग गायब हैं। एक घर में बंद करके महिला, बच्चों को जलाया गया। पहले भी ऐसी घटना हुई है। चुनावों में भी सत्तारूढ पार्टी का दबदबा है उन्होंने कहा कि पूरे देश में ऐसी घटना नहीं हुई है। सीरिया-अफगानिस्तान में ऐसी घटना होती है। दिगर बात हो कि बीरभूम में हिंसा को लेकर भाजपा ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग तक की जा रही है। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने इसे लेकर पलटवार करते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। ममता ने आगे कहा कि बीरभूम में हत्याओं को सही नहीं ठहरा रही हैं, लेकिन यूपी, गुजरात, मध्यप्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ऐसी कई घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि यह पश्चिम बंगाल है उत्तरप्रदेश नहीं, इसीलिए यहां आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सनद् रहे कि इस हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के प्रति संवेदना है। ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा को 'जघन्य पाप' करार देते हुए इस पर दुख प्रकट किया और उम्मीद जताई कि राज्य सरकार दोषियों को जरूर सजा दिलाएगी। कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में नवनिर्मित विप्लवी भारत दीर्घा का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को आश्वस्त किया कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वह चाहेगी, केंद्र सरकार उसे मुहैया कराएगी। बीरभूम जिले में हुई हिंसा की घटना का उल्लेख करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने कहा कि ''मैं इस हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं... अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।'' उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। प्रधानमंत्री ने बंगाल की जनता से आग्रह किया कि वह ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले लोगों और ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेंगी, उसे मुहैया कराई जाएगी। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता

व राज्य सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि राज्य सरकार कानून को अपना काम करने देना सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य से बंधी है। दोषियों को ढूंढा जाएगा और सजा दी जाएगी।

ज्ञात हो कि रामपुरहाट के बोगतुई गांव में तड़के करीब एक दर्जन मकानों में कथित तौर पर आग लगा दिए जाने से जल कर मौत हो गयी। यह घटना तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पंचायत स्तर के नेता भादू शेख की कथित हत्या के कुछ घंटों के भीतर हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इस हिंसा के लिए राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समर्थित 'गुंडों' को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बीरभूम जिले में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हों। इस हिंसा की घटना के सिलसिले में अब तक कम से कम 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वही बताते चले कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोर देते हुए कहा कि बीरभूम जिले में हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीरभूम जिले के एक गांव में 22 मार्च को कथित तौर पर कुछ मकानों में आग लगा दी थी, जिसमें 13 लोगों की जल कर मौत हो गई। ममता ने कहा कि वे स्थिति का जायजा लेने के लिए बोगतुई गांव का दौरा करेंगी, जहां एक ग्राम पंचायत उप प्रधान की हत्या के शीघ्र बाद कुछ मकानों में आग लगा दी गई थी। ममता ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा, वाम दलों और कांग्रेस की कोशिश है। बीरभूम की घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि

हमने थाना प्रभारी, उपसंभागीय पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया है। पुलिस महानिदेशक भी जिले में ही हैं। मुख्यमंत्री ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान यह भी कहा कि उन्हें जिले का अपना दौरा एक दिन के लिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि वहां पहले से जुटे हुए अन्य राजनीतिक दलों के साथ वह नहीं उलझना चाहती थीं। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता घटनास्थल पर जाते समय लंगचा (पड़ोसी बर्दवान जिले के शक्तिगढ़ क्षेत्र में बनने वाली मिठाई का स्वाद लेने के लिए रुक गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कल (बोगतुई गांव) जाऊंगी। मैं आज ही वहां गई होती, लेकिन कुछ राजनीतिक दल के लोग वहां जा रहे हैं। उनके लौटने तक मेरे जाने में देर हो जाती। जब वे (विपक्षी नेता) वहां होते, तब मैं वहां नहीं जाना चाहती। मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहती। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि उन्हें लंगचा का स्वाद लेने दीजिए और फिर रामपुरहाट जाने दीजिए। ममता ने अन्य राज्य में हिंसा की पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के सांसदों को असम में हवाईअड्डे पर रोक दिया गया था, जहां वे एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) का विरोध करने गये थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सांसदों को उत्तर प्रदेश में हाथरस और उन्नाव (जहां सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई थी) में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं दी गई थी, लेकिन उनकी सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह बंगाल है, उत्तर प्रदेश

नहीं। हमने हर किसी को बीरभूम जाने दिया। उन्होंने कहा कि मैं बीरभूम हिंसा का बचाव नहीं कर रही, लेकिन इस तरह की घटनाएं उप्र, गुजरत, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में अक्सर हुआ करती हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हालांकि कहा है कि उन्हें और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों को घटनास्थल पर जाने से रोका गया। बनर्जी ने कार्यक्रम के दौरान आरोप लगाया कि हिंसा की ऐसी घटनाएं पेट्रोल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि जैसे चिंताजनक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रची गई साजिश का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मीडिया को इस (बीरभूम हिंसा) पर शोर-शराबा करते रहने को कहा है। वही राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए ममता ने कहा, ''एक लाट साहेब यहां बैठे हुए हैं और बंगाल को सबसे खराब राज्य बता रहे हैं...राज्य सरकार की बुराई कर रहे हैं।'' भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घटनास्थल का दौरा करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें चार सांसद शामिल हैं।

रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के लिए पहचाना जाने वाला पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिला इन दिनों रामपुरहाट की दिल दहलाने वाली घटना के कारण सुर्खियों में है। इस घटना के बाद सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गए हैं। इस घटना से स्थानीय लोग इतने खौफ में हैं कि अपने घरों को ही छोड़कर जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि यदि पुलिस ने सुरक्षा दी होती तो शायद यह घटना घटीत होती ही नहीं। वही कहा जा रहा है कि रामपुरहाट में टीएमसी के उपप्रधान की हत्या का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही शेख स्टेट हाईवे 50 पर टीएमसी के पंचायत स्तरीय नेता भादू शेख पर बम से हमला किया गया था। इस हमले में शेख की मौत हो गई। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि भादू की हत्या अवैध खनन से जुड़ी कमाई को लेकर हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस तरह की घटना की आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी। इस पूरे कांड में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह पूरा मामला टीएमसी समर्थक दो परिवारों और उनके समर्थकों के बीच आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। बता दें कि

रामपुरहाट कस्बे के बाहरी इलाके बोगतुई गांव में हुई इस बर्बर घटना ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सुरक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है, वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना में मृत लोगों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार, बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मोदी ने टीएमसी पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा कि मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। वहीं, ममता ने कहा कि सरकार हमारी है हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी की भी मृत्यु हो। रामपुरहाट की घटना दुर्भाग्पूर्ण है। तृणमूल कांग्रेस ने हिंसा में शामिल होने से इनकार किया है। हालांकि ममता ने यह कहकर इस मामले पर पानी डालने की कोशिश की है कि ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में अक्सर होती हैं।

बहरहाल, बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास काफी पुराना है। पिछले साल भी विधानसभा चुनाव के दौरान भड़की हिंसा में 16 लोगों की जान गई थी। एक जानकारी के मुताबिक 1977 से 2007 तक पश्चिम बंगाल में 28 हजार राजनीतिक हत्याएं हुईं। सिंगूर

और नंदीग्राम का आंदोलन भी राजनीतिक हिंसा का ही एक नमूना था। ऐसी ही कई अन्य घटनाएं भी हैं, जो दर्ज ही नहीं हुईं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2013 से लेकर मई 2014 के काल में बंगाल में 23 से अधिक राजनीतिक हत्याएं वहां पर हुईं। 2016 में राजनीतिक कारणों से हुई हिंसक घटनाओं में 205 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह 2018 में पंचायत चुनाव के दौरान एक दिन में 18 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अलबत्ता इस घटना पर पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 26 मर्डर हुए, हमारे सांसद पर बम से हमला किया गया, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी गोलियां और बम चल रहे हैं। बंगाल के एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर गोली और बम नहीं चलेंगे तो पुलिस और कोर्ट क्या करेगा? मजूमदार ने इस मामले में केन्द्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बीरभूम एक संवेदनशील क्षेत्र है, जहां राजनीतिक हिंसा अपने चरम पर है। हर दिन विपक्षी दलों को निशाना बनाया जाता है। राज्य में 200 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर दिलीप घोष ने सवाल किया कि ममता सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में रामपुर हाट जैसी घटनाएं नहीं होतीं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा कि रामपुरहाट में टीएमसी के उपप्रधान की हत्या का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। तृणमूल समर्थक आरोपियों ने 5 घरों के दरवाजे बंद कर आग लगा दी। क्या बंगाल की जनता ने आपको (तृणमूल कांग्रेस) इनके लिए चुना है। इस बाबत कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने ममता सरकार को बीरभूम के रामपुरहाट में आगजनी की घटना पर 24 घंटे के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सरकार को सख्त निर्देश दिए थे कि मौके पर सबूत नष्ट नहीं होने चाहिए। साथ ही कहा कि केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से एक टीम आगजनी की घटना के नमूने एकत्र करने के लिए भेजी जाएगी। वही इस मामले में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री एक बार फिर आमने सामने हैं। राज्यपाल ने जहां इस घटना को भयानक हिंसा और आगजनी का तांडव और राज्य में कानून व्यवस्था की नाक में दम करने वाला करार दिया तो दूसरी तरफ ममता ने पत्र लिखकर राज्यपाल पर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि निष्पक्ष जांच का मार्ग प्रशस्त करने के बजाय व्यापक और अनावश्यक बयान देना बेहद अनुचित है। उन्होंने राज्यपाल से अनुचित बयान से परहेज करने का अनुरोध किया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने में जुटी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस घटना ने बैकफुट पर ला दिया है। वे भाजपा समेत अन्य विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई हैं। घटनास्थल का दौरा करने और पीड़ितों से मिलने के बाद सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने कहा कि हिंसा मामले में कुछ छिपाया जा रहा है। लोकसभा में भी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन

चौधरी ने संसद में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं और बच्चों को जिंदा जलाने की ऐसी भयावह घटनाएं हो रही हैं।

ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में 3 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 8 लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटा गया था। मृतकों के शवों की पोस्टमार्टम जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। रामपुरहाट अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम और अन्य जांच करने वाले फॉरेंसिक विशेषज्ञों के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार पीड़ितों को पहले बुरी तरह पीटा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। रामपुरहाट के बोगतुई गांव में 22 मार्च को तड़के करीब एक दर्जन मकानों में आग लगा देने से 2 बच्चों समेत कुल 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। यह घटना 21 मार्च को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पंचायत स्तर के नेता भादू शेख की कथित हत्या के कुछ घंटों के भीतर हुई। तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या के बाद रामपुरहाट शहर के बाहरी इलाके में स्थित बोगतुई गांव में करीब एक दर्जन मकानों पर कथित तौर पर पेट्रोल बम से हमला कर आग लगा दी गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने अपने नेता की हत्या के प्रतिशोध में मकानों में आग लगा दी। पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कथित रूप से लापरवाही बरतने के आरोप में कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी,

चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के क्यों न हों। कांग्रेस की बंगाल इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी और भाजपा की 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम भी बोगतुई गांव का दौरा करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (CID) ज्ञानवंत सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ध्यान रहे कि बीरभूम में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए राज्यसभा में भाजपा सांसद रूपा गांगुली रो पड़ीं। रूपा ने कहा कि बंगाल में हालात रहने लायक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोग बोल नहीं सकते। हत्यारों को तृणमूल सरकार संरक्षण दे रही है। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की। खबरों के अनुसार, राज्यसभा में पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुए नरसंहार पर बोलते हुए भाजपा सांसद रूपा गांगुली भावुक हो गईं और इस बीच उनके आंसू छलक पड़े। रूपा ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। वहां सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, लोग वहां से भाग रहे हैं। बंगाल अब रहने लायक नहीं है। रूपा ने राज्य सरकार पर साजिशकर्ताओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बंगाल में लोग बोल नहीं सकते। हत्यारों को तृणमूल सरकार संरक्षण दे रही है। कोई ऐसा दूसरा राज्य नहीं है, जहां चुनाव जीतने और सरकार बनने के बाद इतनी अधिक संख्या में लोग मारे गए हों। हम इंसान हैं, हम पत्थरदिल वाली राजनीति नहीं करते। वही पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य में बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हुई हत्या की सीबीआई जांच को भाजपा प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। भगवा पार्टी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने 22 मार्च की घटना के बाद अपनी विश्वसनीयता खो दी है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा कई साल पहले गुजरात में हुई हत्याओं को भूल गई है। अब बोगतुई की घटना पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, जिसमें पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। हम दोहराना चाहते हैं कि राज्य सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, भले उनका संबंध किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना के दो दिन के भीतर घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मिलीं। हम पारदर्शी, निष्पक्ष और शीघ्र सीबीआई जांच को लेकर सहज हैं। हालांकि, गत एक-दो दिनों में भाजपा द्वारा अपने राजनीति हित के लिए केंद्रीय एजेंसी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश के संकेत मिले। हम ऐसे किसी कदम का विरोध करते हैं। घोष ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी इंतजार करेगी और देखेगी कि कैसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच की प्रगति हो रही है, अगले कुछ दिनों में हम भविष्य की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा कि हम हरसंभव तरीके से सीबीआई जांच में सहयोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने बोगतुई की घटना के बाद अपनी विश्वसनीयता खो दी है। उन्होंने इसके साथ ही तृणमूल के आरोपों पर भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

AAP councilor cleans up sewage drain, takes milk bath later

A video of AAP councilor Haseeb-ul-Hasan from East Delhi is going viral wherein he can be seen standing chest deep inside an overflowing sewage drain and cleaning the floating debris using a rake. After the clean-up, Hasan's supporters gave him a bath in milk, much in the style of actor Anil Kapoor in Bollywood blockbuster "Nayak". Hasan said the drain was overflowing and even after repeated complaints to officials, the BJP councilor and the local MLA didn't help. So he decided to take matters in his own hands.

Meanwhile, the Union Cabinet on Tuesday cleared a proposal to merge the three municipal bodies in Delhi. Informed sources said the government would bring an amendment bill to unify the three municipalities in the ongoing Budget session of Parliament. The decision was taken in order to strengthen the management and finances of the South Delhi Municipal Corporation (SDMC), the North Delhi Municipal Corporation (NDMC) and the East Delhi Municipal Corporation (EDMC), the sources said. The Congress government in 2011 had trifurcated the municipal corporation by passing the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill.

The decision to merge the three civic bodies into one has come nearly a fortnight after the State Election Commission deferred the announcement for municipal polls, drawing sharp reactions from the Aam Aadmi Party (AAP) which has since moved the Supreme Court. All three MCDs are currently ruled by the BJP but the AAP is hopeful of snatching them in the upcoming polls.

आ रहा नया कानून

आंखों के रेटिना से पैर के प्रिंट तक रखा जायेगा अपराधी का हर रिकॉर्ड

संसद का बजट सत्र जारी है. 14 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र 8 अप्रैल को खत्म होगा। इस सत्र में अबतक बहुत सारे अहम बिलों पर चर्चा हुई है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया गया, ''आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022'', उसपर संसद में खूब हंगामा हुआ। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी ने सदन में इस बिल को पेश किया, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने इस बिल पर कड़ी आपत्ति जताई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी समेत विपक्षी दलों के कई अन्य नेताओं ने भी विरोध जताया। इस दौरान देर तक हंगामा हुआ। फिलहाल संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में इसे पटल पर रखा गया है. बहस के बाद यहां से पास होने के बाद इसे उच्च सदन राज्यसभा भेजा जाएगा. राज्यसभा में पास होने के बाद यह बिल अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और फिर यह कानून का रूप ले लेगा. इसके अस्तित्व में आते ही एक पुराना कानून 'द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920' डिजॉल्व हो जाएगा और यह नया कानून उसकी जगह ले लेगा। आइए जानते हैं, इस संबंध में अबतक क्या कानून था, इस नए आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) बिल में क्या है, इसपर विपक्ष की क्या आपत्ति है और क्यों विवाद हो रहा है।

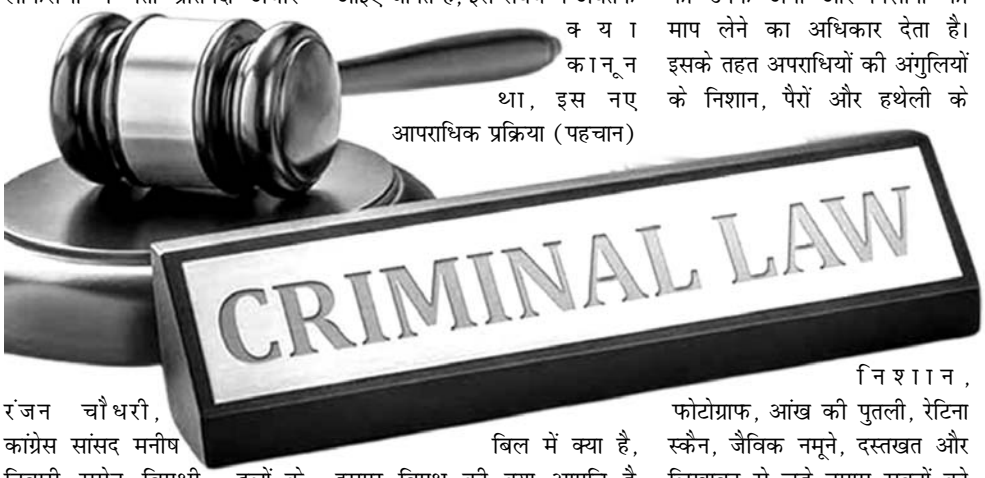

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक अपराधियों की यूनीक पहचान से जुड़ा विधेयक है, जिसका उद्देश्य अपराधियों की बायोग्राफिक डिटेल्स को सुरक्षित रखना है। इस बारे में संसद टीवी में लंबे समय से कार्यरत सूरज मोहन झा के द्वारा एक निजी चैनल को बताया कि इस बिल को लाने का मकसद अपराधियों की पहचान को संरक्षित करना है, जो भविष्य में भी काम आ सके। उन्होंने बताया कि यह बिल अपराधियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए पुलिस को उनके अंगों और निशानों की माप लेने का अधिकार देता है। इसके तहत अपराधियों की अंगुलियों के निशान, पैरों और हथेली के निशान, फोटोग्राफ, आंख की पुतली, रेटिना स्कैन, जैविक नमूने, दस्तखत और लिखावट से जुड़े तमाम सबूतों को संरक्षित रखा जाएगा।

अपराधियों की पहचान से जुड़े मामलों की बात करें तो वर्तमान में 'द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920' लागू है। यह काफी पुराना है और अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है। इस कानून की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि इस कानून के तहत यह अपराधियों के केवल फिंगर और फुटप्रिंट लेने की ही इजाजत है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं। नया बिल कानून बनने के बाद 'द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920' की जगह लेगा। कानून बनने के बाद किसी भी मामले में दोषी पाए गए या गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान के लिए पुलिस अधिकारियों को हर तरह (ऊपर मेंशन) की माप लेने का अधिकार होगा/इजाजत होगी। किसी अपराध के मामले में गिरफ्तार और दोषसिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है।

संसद के निचले सदन में 58 के मुकाबले 120 मतों से विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी गई। इस विधेयक को हाल में

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। विधेयक पेश करते हुए गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि मौजूदा अधिनियम को बने 102 साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उसमें सिर्फ फिंगर प्रिंट और फुटप्रिंट लेने की अनुमति दी गई, जबकि अब नई प्रौद्योगिकी आई है और इस संशोधन की जरूरत पड़ी है। उन्होंने कहा कि यह छोटा विधेयक है। इससे जांच एजेंसियों को मदद मिलेगी और दोषसिद्धि भी बढ़ेगी। कानून मंत्रालय और सभी संबंधित पक्षों के साथ लंबी चर्चा के बाद यह विधेयक लाया गया है। मिश्रा ने विपक्ष के सदस्यों की आपत्ति के जवाब में कहा कि मौजूदा प्रस्ताव किसी भी दृष्टि से मनमाना नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जब लखीमपुर खीरी मामले को लेकर मिश्रा पर कुछ टिप्पणी की तो मिश्रा ने कहा कि मैंने 2019 में नामांकन पत्र भरा था। अगर मैं एक भी मिनट के लिए जेल गया हूं, मेरे खिलाफ एक भी मामला हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस बीच विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस सदन को यह चर्चा करनी चाहिए कि क्या सत्तापक्ष को यह अधिकार है कि वह ऐसा विधेयक लाए जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात करता हो। आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन ने आरोप लगाया कि इस विधेयक के जरिए संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए मेरे खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है तो मेरा डीएनए जांचा जाएगा। इसका क्या मतलब है? यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि अगर यह कानून यहां से पारित होता है तो यह न्यायपालिका में नहीं ठहर पाएगा। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि फिंगर टेस्ट करने और जैविक नमूने लेने की क्या जरूरत है? क्या अपराध अचानक से बढ़ गया है? यह विधेयक मानवाधिकारों का हनन करता है और संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि गृह मंत्री

(अमित शाह)

इस बारे में समझाएं। टेनी जी क्या समझाएंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश की शीर्ष अदालत ने पुट्टूस्वामी मामले में जो निजता के अधिकार की बात कही थी, यह विधेयक उसका उल्लंघन करता है और यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। बसपा के रितेश पांडे ने कहा कि संविधान में नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उनका हनन हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार चाहती है कि लोगों को भय में रखा जाए। पांडे ने कहा कि नागरिकों के ऊपर मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है कि लोग अपने अधिकारों की बात करने से डरें। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पेश करने पर मत-विभाजन की मांग की। इसके बाद हुए मत-विभाजन में विधेयक पेश करने की अनुमति दिए जाने के पक्ष में 120 वोट पड़े तथा 58 मत विरोध में पड़े। इस विधेयक के माध्यम से वर्ष 1920 के कैदियों की पहचान संबंधी कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। औपनिवेशिक ब्रिटिश काल के वर्तमान कानून में उन दोष सिद्ध अपराधियों और अपराध के मामले में गिरफ्तार लोगों के शरीर के सीमित स्तर पर माप की अनुमति दी गई है, जिसमें एक वर्ष या उससे अधिक सश्रम कारावास का प्रावधान होता है। इस विधेयक में दोषियों और अपराध के मामले में गिरफ्तार लोगों का विभिन्न प्रकार का ब्योरा एकत्र करने की अनुमति देने की बात कही गई है जिसमें अंगुली एवं हथेली की छाप या प्रिंट, पैरों की छाप, फोटो, आंखों की पुतली, रेटिना और लिखावट के नमूने आदि शामिल हैं। सरकार का मानना है कि अधिक से अधिक ब्योरा मिलने से दोष सिद्धि दर में वृद्धि होगी और जांचकर्ताओं को अपराधियों को पकड़ने में सुविधा होगी।

अपराधियों पर शिवराज का बुलडोजर

उत्तरप्रदेश चुनाव में बुलडोजर की खूब चर्चा रही। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा नाम भी दिया गया। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बुलडोजर का खौफ यूपी के अपराधियों में अब और बढ़ने लगा है। कहीं बुलडोजर चल रहा है तो कहीं बुलडोजर के डर से अपराधी सरेंडर कर रहे हैं। यूपी की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश में भी अपराधियों के अवैध निर्माणों को बुलडोजर से तबाह किया जा रहा है। हाल ही मध्यप्रदेश में अपराधियों के निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। महू के पिगडम्बर में आरोपितों के निर्माणों को बुलडोजर से ढहाया गया। मुख्यमंत्री के रूप में अपने चौथे कार्यकाल के दो साल पूरे कर चुके सीएम शिवराज सिंह का फिर से एग्रेसिव अंदाज देखने को मिला. प्रदेश में मामा की कोमल छवि वाले सीएम शिवराज इन दिनों बुलडोजर मामा बनकर अपराधियों पर कहर बरपा रहे हैं. यूपी में सीएम योगी की बुलडोजर बाबा की सफलता के बाद एमपी में 2023 से पहले सीएम भी आक्रामक अवतार अपना रहे हैं. अपराध और अपराधियों को लेकर सीएम के इस नए अवतार की हर जगह चर्चा हो रही है.

बुलडोजर को लेकर बढ़ते खौफ के बीच ये जानना जरूरी है कि बुलडोजर कब और कैसे चलता है? इसके नियम क्या हैं? यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक कानूनी तौर पर बुलडोजर दो परिस्थितियों में चलता है। पहले जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर उस पर अपना निर्माण करा ले। इस स्थिति में उस सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए अवैध निर्माण को गिराया जाता है। इसके लिए बाकायदा लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम, तहसीलदार से लेकर जिला प्रशासन की रिपोर्ट लगाई जाती है। स्थानीय पुलिस बल को तैनात किया जाता है। तब बुलडोजर सरकारी जमीन पर बने निर्माण को गिराने के लिए पहुंचता है।

दूसरी स्थिति में बुलडोजर तब चलाया जाता है जब अपराध करने के बाद अपराधी लगातार भाग रहा हो। जब अपराधी कानूनी प्रक्रिया और वारंट के बाद भी सरेंडर नहीं करता है तब प्रशासन उसकी अपराध से कमाई संपत्ति पर कुर्की का आदेश लेने के बाद बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाती है। उत्तरप्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक इसके लिए जरूरी है कि वो संपत्ति अपराध की कमाई से बनाई गई हो। दूसरी तरफ शिवराज सरकार के इस कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर एमपी में नया नारा सुनने को मिला. हर जगह बुलडोजर मामा जिंदाबाद के नारे लगे. इस बीच मीडिया से चर्चा में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि बहन बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वालों के लिए सामान्य सजा काफी नहीं है. उनकी

जमानत होती है, फिर आ गए. लेकिन हम अब ऐसा सबक सिखाएंगे की ऐसे अपराधी कांप जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को परेशान करने वाले, जमीनों पर कब्जा करने वाले, जो मां बहन बेटी की तरफ गलत नजर उठाएंगे, उनको कानून सजा देगा लेकिन बुलडोजर भी चलेगा और उनकी प्रॉपर्टी जमीदोंज कर दी जाएगी. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने अपने चौथे कार्यकाल में दो साल पूरे कर लिए. इस मौके पर भोपाल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया. 15 महीने की कांग्रेस सरकार के गिरने के बाद 23 मार्च, 2020 को शिवराज सिंह ने चौथी बार सत्ता की कमान अपने हाथों में ली. इसके बाद सीएम ने किसानों, आदिवासियों और महिला

सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए. इस कार्यकाल में उनकी काफी योजना महिलाओं पर केंद्रित दिखीं. सीएम की पूरी रणनीति 2023 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बन रही है. इसी कड़ी में प्रदेश के मामा से बदलकर बुलडोजर मामा की छवि जनता के सामने लाई जा रही है और ये पसंद भी की जा रही है. आमजन अपराधियों पर इसी तरह की कड़ी कार्रवाई चाह रहा है.

IAF rescues young trekker who fall 300 ft from mountain cliff in Karnataka's Nandi Hills

Indian Air Force on Sunday saved a young trekker stuck in Bramhagiri Rocks in Nandi Hills after slipping and falling 300 feet below. The trekker had fallen at around 4.15 pm. A Mi17 helicopter was promptly launched and after an intense search and with the ground guidance of local police, IAF said in a statement here. The terrain being treacherous for a landing, the Flight Gunner of the Mi17 was daringly lowered by winch next to the survivor. The flight gunner helped the survivor to harness and winched up safely. The on-board Air Force medical assistant attended to the survivor while the helicopter flew him to Air Force Station Yelahanka from where the survivor was taken to the nearest Civil hospital by 6 pm. The Air Force swung into action after Chikballabpur Deputy Commissioner contacted them with an SOS message about a young trekker stuck in Bramhagiri Rocks.

कश्मीरी पंडितों की वापसी प्राथमिकता है पर माहौल अब भी सुरक्षित नहीं

● सुरेश एस. डुग्गर

32 सालों से अपने ही देश में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे लाखों कश्मीरी विस्थापितों का यह दुर्भाग्य है कि उनकी कश्मीर वापसी प्रत्येक सरकार की प्राथमिकता तो रही है लेकिन कोई भी सरकार फिलहाल उनकी वापसी के लिए माहौल तैयार नहीं कर पाई है। वर्तमान सरकार के साथ भी ऐसा ही है जिसका कहना है कि कश्मीर में सुरक्षा हालात फिलहाल ऐसे नहीं हैं कि कश्मीरी विस्थापितों को वापस लौटाया जा सके। 1989 के शुरू में आतंकी हिंसा में तेजी ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी का त्याग करने पर मजबूर कर दिया। सरकारी आंकड़ों के बकौल, पिछले 32 सालों में हजारों परिवारों के तकरीबन 3.5 लाख सदस्यों ने कश्मीर को छोड़ दिया। हालांकि अभी तक सभी सरकारें यही कहती आई थीं कि कश्मीरी पंडितों ने आतंकियों द्वारा खदेड़े जाने पर कश्मीर को छोड़ा था। मुफ्ती मुहम्मद सईद की सरकार ऐसा नहीं मानती थी जिसके सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में कश्मीरी विस्थापितों की वापसी प्राथमिकता पर तो थी। लेकिन इस सरकार ने कई सालों के अरसे के बाद नया शगूफा छोड़ा था कि कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से कश्मीर से गए थे और किसी ने उन्हें नहीं निकाला था। 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर का त्याग आप किया या फिर आतंकियों ने उन्हें खदेड़ा था, यह बहस का विषय है लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे अहम प्रश्न यह है कि दावों के बावजूद कश्मीरी पंडितों की वापसी का माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है। वर्तमान केंद्र सरकार के दावों पर जाएं तो कश्मीर का माहौल बदला है। फिजां में बारूदीं गंध की जगह केसर क्यारियों की खुशबू ने ली है। पर बावजूद इसके कश्मीर की कश्मीरियत का अहम हिस्सा समझे जाने वाले कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए माहौल नहीं है। ऐसा प्रदेश और केंद्र सरकारों के दस्तावेज भी कहते हैं। ऐसा माहौल 32 सालों के बाद भी क्यों नहीं बन पाया है कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता।

प्रशासन के मुताबिक सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है तो प्रशासन कहता है कि कश्मीरी विस्थापितों की वापसी तभी संभव हो पाएगी जब उनके जल और टूट-फूट चुके घरों की मरम्मत होगी। प्रशासन को इसके लिए कई सौ करोड़ रूपयों की जरूरत है। यह रूपया कहां से आएगा कोई नहीं जानता। यूं तो केंद्र सरकार भी कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करने को तैयार रहने का दावा करता रहा है पर रूपयों की बात आती थी तो केंद्र की प्रत्येक सरकार ने हमेशा ही चुप्पी साधी है इन बरसों में। वर्तमान प्रशासन के कई अधिकारी भी इसे स्वीकारते हैं कि कश्मीरी विस्थापितों की वापसी के लिए पहले जमीनी वास्तविकताओं का सामना करना होगा जिनमें उनके वापस लौटने पर उनके रहने और फिर उनकी सुरक्षा का प्रबंध करना भी कठिन कार्य है। वैसे भी ये मुद्दे कितने उलझे हुए हैं यह इसी से स्पष्ट है कि विस्थापितों की वापसी को आसान समझने वाले अपने सुरक्षा प्रबंध पुख्ता नहीं कर पा रहे हैं तो साढ़े तीन लाख लोगों को क्या सुरक्षा दे पाएंगें वे कोई उत्तर नहीं देते। कश्मीरी विस्थापित अपने खंडहर बन चुके घरों में लौटेंगें या नहीं, अगर लौटेंगें तो कब तक लौट पाएंगें इन प्रश्नों के उत्तर तो समय ही दे सकेगा मगर इस समय इन विस्थापितों के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न वापसी और सम्मानजनक वापसी का है। ऐसा भी नहीं है कि वे कश्मीर में वापस लौटने के इच्छुक न हों मगर उन्हें सम्मानजनक वापसी, अस्तित्व की रक्षा और पुनः अपनी मातृभूमि से पलायन करने की नौबत नहीं आएगी जैसे मामलों पर गारंटी और आश्वासन कौन देगा। अगर वे लौटेंगे तो रहेगें कहां जैसे प्रश्नों से वे 32 सालों से जूझ रहे हैं।

यूक्रेन और रूस का महायुद्ध

विश्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर

● ललन सिंह

रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बहुत पहले शुरू हुआ था जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का राजधानी कीव में विरोध शुरू हुआ। उनको रूस का समर्थन था, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका के समर्थित प्रदर्शनकारियों के लगातार विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा था, वर्तमान में रूस की युद्धनीति यूक्रेन पर हमले के कदम उठाने के कुछ कारणों से अवगत होना भी जरूरी है। इसमें सबसे बड़ी वजह अमेरिका द्वारा यूक्रेन के नाटो संगठन में शामिल करने की कवायद है। नाटो में अमेरिका का वर्चस्व है। इस संगठन में 30 देश शामिल है एवं अधिकतर देश यूरोप के ही है। इस संगठन में सबसे अधिक फौजी जवान अमेरिकन हैं। नाटो को हिन्दी में उत्तरी अंटलांटिक संधि संगठन और अंग्रजी में नॉर्थ अंटलांटिक टीरीटी ऑर्गनाइजेशन कहते हैं। यह एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इस संगठन का मुख्यालय वुसेल्स (बेलजियम) में है। इसकी व्यवस्था का आधार सामुहिक सुरक्षा पर आधारित है, जिसके तहत बाहरी आक्रमण होने पर इस संगठन के सभी देशों को सहमति एवं सहयोग और आपसी तालमेल द्वारा मुकाबला करने का है। नाटो का सैन्य रणनीति का उद्देश्य ही अपने संगठन के देशों के ताकत से मजबूत सुरक्षात्मक माहौल बनाने का है, जिससे पूरे विश्व में ताकत वाला संगठन नाटो को मान्यता है।

विक्टर यानुकोविच

यूक्रेन कभी रूसी सम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली और तभी से यूक्रेन रूस के छत्रछाया से निकलने की लगातार कोशिश करने लगा और तभी से यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से नजदिकियां बढ़ाई। यूक्रेन की उत्तर एवं पूर्वी हिस्से की लंबी सीमा रूस से मिलती है और 2010 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने तो रूस से करीबी रिश्ते बनने लगे। उन्होंने ही यूरोपीय संघ में शामिल होने के समझौते को खारिज भी किया था और इसी कारण से भारी विरोध के वजह से

वलोडिमिर जेलेंस्की

जो बाइडेन

व्लादिमीर पुतिन

2014 में इस्तिफा देना पड़ा। यूक्रेन द्वारा लगातार रूस पर आरोप लगता रहा कि वे अलगाववादियों और विद्रोहियों को हथियार के साथ ही आर्थिक रूप से मदद दी जाती रही है और बाद में रूस द्वारा यूक्रेन के ऊपर आक्रमकता की कार्यवाही हुई और क्रीमिया प्रायादीप पर कब्जा किये गये पूर्वी हिस्से में यूक्रेन के डोनावास जो औद्योगिक इलाका है, 2014 के लड़ाई में 14000 से अधिक लोगों की जानें भी गई थी। हालांकि जर्मनी और फ्रांस द्वारा शांति और विवादों के समाधान के लिए किये गये मध्यस्था भी यूक्रेन एवं रूस के बीच कई बार हुई जंग तो उस समय रूक गया, पर पूरी तौर पर कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकल पाया और यह चिंगारी दोनो देशों के बीच में धीरे-धीरे लड़ाई के कारण भी बनने में रही, इस बात में कोई संदेह नहीं।

पिछले साल से ही दोनों देशों में संघर्षविराम कें उल्लंघन के हालात में तेजी आने लगे थे, फिर यूक्रेनी सीमा के नजदीक रूसी सैनिकों का युद्धाभ्यास शुरू हुआ। बीच-बीच में रूस ने युद्धाभ्यास को रोका भी, जिससे तनाव में कमी भी आयी, पर अचानक रूस द्वारा रूस-यूक्रेन सीमा के नजदीक 1 लाख 75 हजार जवानों की तैनाती कर दी। इस हालात के मद्देनजर अमेरिका एवं नाटो देशों के अनावश्यक बयानों से और माहौल को बिगाड़ने में समर्थन मिला। आज जो यूक्रेन की तबाही का जो हालत है, उसमें रूस के साथ अमेरिका एवं उसके सहयोगी देश भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। सच है कि युद्ध विनाश के सबसे बड़ा कारण है। आज भी अमेरिका एवं ब्रिटेन, रूस के हमले पर भारत को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका एवं नाटो के सदस्य देश और इन देशों की मीडिया पुतीन महोदय को ही खलनायक बताने में जुटा है। यह बात भी सच है कि यूक्रेन एक संप्रभु देश है, लेकिन उसे रूस की सुरक्षा चिंताओं का भी ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि रूस बार-बार यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने के लिए दबाब और चेतावनी दे रहा था। रूस का कहना था कि अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए पर अमेरिका अपने सुपर पावर वाले सोच के कारण यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने पर आमदा था। सच यह भी है की नाटो का संगठन सोवियत संघ के साम्यवाद का विस्तार को रोक लगाने के लिए किया गया था। 1991 के सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके नेतृत्व वाले बरसा पैक्ट का वजूद भी खत्म हो गया था और रूस के लगातार चेतावनी के बाद भी नाटो अपने विस्तार के दायरे को बढ़ाने में कार्यरत्त रहा। बरसा पैक्ट का हिस्सा रहे देशों को भी नाटों के संगठन में हिस्सा बनाये और नाटो का हिस्सा बनाने के चाहटत पर रूस अमेरिका और नाटो के देशों को दूरी बनाने के लिए चेताया भी, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कई बार यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो देशों के साथ सैन्य अभ्यास को भी जारी रखा और आज यूक्रेन और रूस की इस भयंकर युद्ध की वजह से यूरोपीय देशों और अमेरिका का अनावश्यक समर्थन भी रहा, इस बात पर संदेह नहीं और इन कारणों का परिणाम है की विश्व आज परमाणु खतरे और तीसरे विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है, जो की पूरे दुनियां

के लिए चिंता का विषय है। इन हालातों पर रूस के उपर भी यूक्रेन द्वारा लगातार आरोप भी लगते रहे हैं की विद्रोहियों के गढ़ में रूसी सैनिकों की मौजूदगी है। रूस इन बयानों को खारिज भी करता रहा है पर रूसी राष्ट्रपति कई बार यूक्रेनियों और रूस के लोगों को एक ही लोग मानने वाले बयान देते रहे हैं और यह भी कहा है कि सोवियत संघ के समय में यूक्रेन को गलत तरीके से रूसी जमीन मिल गया था। इस हालात में दोनो देशों में लगातार एक-दूसरे पर अरोप-प्रत्यारोपों का बयान जारी रहता रहा है और इन वजहों से सीमा विवाद और तानातानी अपने चरम ऊँचाइयों पर पहुंचा और आज दोनो देश अपने एक्शन से महायुद्ध के कगार पर है और महाविनाश जारी है।

एक और चिंता रूस को थी की नाटो अपना सैन्य मजबूती के बाबत यूक्रेन में नाटो का ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए तैयारी कर रहा है। यदि नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं भी हुआ तो भी यह नाटो का सोच रूसी क्षेत्र के नजदीक खतरा पैदा कर सकता है और पुतीन महोदय लिखित में गारंटी चाहते थे की यूक्रेन में किसी तरह का नाटो का सैन्य मजबूती का कार्यक्रम ना तो इसके लिए राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच वर्चुअल बैठक भी हुई थी, पर बाइडेन साहब ने इन रूस के चिंताओं प र गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। संवाद और वार्ता की कमी के कारण यूक्रेन एवं रूस के आपसी मतभेद और एक-दूसरे पर अविश्वास बढ़ता गया। तनाव एवं लड़ाई के हालात बनने लगे और इस वर्ष के फरवरी 24 तारीख से खुलकर युद्ध का शुरूआत हो गया। इसमें रूस के द्वारा पहल हुई। दो प्रांतों को स्वतंत्र देश एवं उसके साथ एक्शन के प्रस्ताव ने माहौल को पूरी तरह से महायुद्ध में बदल कर रख दिया और आज इस महाविनाश युद्ध के त्रासदी से लगभग 15 लाख लोगों का यूक्रेन से पड़ोसी देशों में पलायन हो चुका है। हर दिन लोगों की मौते हो रही है। बर्बादी और बिगड़ते हालात पर विश्व और यू.एप.ओ. भी लाचार महसूस कर रहा है, दुनियां दो भागों में बंट रहा है, पर सच यह भी है कि हर को अपना स्वार्थ और हित का ख्याल अधिक है। मानव जाति इस दुखद स्थिति पर कुछ नहीं कर पा रहा, पर शांति हो, इसकी कोशिश जरूर हो रही है, पर हालात ज्यों का त्यों ही है।

यह महायुद्ध अब घातक नतीजे वाला और विश्व को गंभीर संकट में डाल रहा है। हथियारों एवं सैनिक साजो-समानों की होड़ बढ़ाने का भी काम कर रहा है और मानवीय मूल्यों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। भारत भी इस युद्ध से चिंतित है और यह स्वभाविक भी है। दुनियां के हर देश अपने हित और रक्षा बजट को बढ़ाने के दबाब में हैं। इसका ताजा प्रमाण चीन के रक्षा बजट की बढ़ोतरी की घोषणा, यह भी चिंता की बात है। क्योंकि भारत का पड़ोसी चीन एवं पाक के नापाक सोच और विस्तारवादी वाली आदतें जगजाहिर है और चीन के इरादों पर भारत की नजर बहुत सतर्क एवं चौकस भी है और यूक्रेन के संकट से भारत भी बहुत कुछ समझ रहा है। हालांकि चीन से अपने सीमा विवाद के बाबत 11 मार्च को कोर कमांडरों के बीच 15वीं दौर की वार्ता चुशूल मोल्डों में होगी, जिसकी आपसी सहमति भी बन चुकी है और भारत इन वार्ता के दौरान हाट स्पिंग, गोगरा इलाके के साथ डेपंसाम से सैनिकों को पीछे हटाने पर भारत का जोर रहेगा। एक तरफा बदलाव की कोशिश स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को चीन को साफ शब्दों में बता दिया गया है। एक बात और साफ है कि यूक्रेन संकट से मिला सबक, युद्ध के लिए तैयार होना होगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के दिशा में तत्काल कई कदम और उठाने होंगे। भारतीय सेना प्रमुख का बयान इस वर्तमान हालात में मायने रखता है। आपातकाल परिस्थिति में देश को अपना सुरक्षा और अपनी कुटनीति पर ही मुस्तैद होना होगा। यह यूक्रेन के हलात से सबक के तौरपर सिख मिला है। इस अनुभव के द्वारा भारत को सामर्थ्यशाली बनना आज की जरूरत है। रक्षा बजट बढ़ाने के दबाब से उन देशों पर अवश्य दबाब

अधिक होगा, जिनके पड़ोसी ताकतवर और विस्तारवाद वाले अदतों से मजबूर हैं। गरीब और विकासशील देशों को ना चाहते हुए भी शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के आयाम से जुड़े कार्यक्रमों के बजाये रक्षा बजट के बढ़ोतरी एवं रक्षा उपकरणों पर खर्च करना निहायत आवश्यक होगा। कोविड संकट से विश्व पूरी तौर पर अभी उभरा भी नहीं है, यह महायुद्ध का संकट पूरे विश्व के आर्थिक हालातों पर भी चोट पहुंचायेगा। प्रतिबंधो के कारण गैस, ऑयल के साथ हर वस्तुओं पर इसका फर्क और बढ़ोत्तरी होना स्वभाविक है और इन सब समस्याओं पर कैसे विश्वव्यापी नियंत्रण हो, इसके लिए दुनियां के ताकतवर देशों और यूएनओ को आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसमें हमारा देश भारत के भी हर मंच और सभी स्तरो पर कार्यरत्त होना होगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा हो रहा है। इसमें सबसे खास बात यह है कि सबसे पहले वर्तमान यूक्रेन एवं रूस के इस महायुद्ध को खत्म करने और विवादों को राजनीतिक एवं कुटनीतिक तथा सामरिक रूप से समाधान का मार्ग जल्द से जल्द तैयार हो। यूक्रेन और रूस के वार्ता का दौर जारी है, पर दोनो देशों के अपने-अपने शर्तों पर अडिग रहने के कारण शांति एवं समस्याओं का समाधान की हालात नहीं बन रही है। विश्व असंमजश वाली स्थिति में है, क्योंकि पूरी दुनियां इस युद्ध के कारण डरा और सहमा हुआ है।

इस समय एक बात साफ है कि यूक्रेन संकट जिस तरह से गहराता जा रहा है उसमें विश्व के आर्थिक माहौल एवं शांति-सुरक्षा का खतरा आवश्यक रूप से विगाड़ने की स्थिति में है, यूक्रेन के हर बड़े शहरों पर लगातार मिसाइल, बम एवं रूसी हमले के कारण मलवे में परिवर्तित हो रहा है और अब रूस राजधानी किव के कब्जे के लिए अपने घेराबंदी के एक्शन में लगा है। यह भी सच है कि जितने भी नाटो देश और अमेरिकी मदद करे पर यूक्रेन की बर्बादी तय है, क्योंकि अमेरिका या नाटो देशों का साथ आर्थिक या हथियारों एवं सैनिक साजो-सामान का हो सकता है, पर उनके फौज यूक्रेन के लिए रूस के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं देने का स्पष्ट बयान दे चुके हैं। पूरे यूक्रेन में लोग रूसी सैन्य दबाब के कारण लगातार पलायन के तरफ हैं। किव और बड़े शहरों से महिलाओं एवं बच्चों के साथ बुर्जुग को निकाला जा रहा है। दोनो देशों के दो, तीन दिनों के युद्ध विराम कुछ शहरों में देने से लोगों को अपने जान बचाने के लिए मौका जरूर मिल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की का बार-बार बंकर से बाहर आकर देशवासियों एवं फौज के मनोबल को बढ़ाना सही है पर सच को झुठलाया नहीं जा सकता। उनके जोश से यूक्रेन के आम आदमी और यूक्रेन के बचाव होना असंभव जैसा ही है। अब उनके कई बयान लाचारी को दर्शाता है। अब वे डोनवास एवं क्रिमीया पर भी रूस से बातचीत को तैयार हैं, पर रूस को भी अपने शर्तों एवं दूसरे देश के सम्मानजनक हालात पर गौर करना होगा। यूक्रेन के कई शहरों में सिजफायर से पूरी राहत नहीं मिलेगी। अब पूरे तौरपर सिजफायर के बाद ही दोनो देश की हालात सम्मान हो सकती है।

अब गुरिल्ला वार की शुरूआत यूक्रेन एवं रूस के बीच शुरू हो चुकी है, जिससे यह लड़ाई लंबी और खतरनाक हालात पैदा कर सकती है और यही कारण है की अब तक रूस जैसा ताकतवर सामरिक दृष्टि से देश यूक्रेन को पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया है और इस युद्ध में रूस का भी काफी नुकसान होता नजर आ रहा है। 1500 करोड़ से अधिक प्रतिदिन का व्यय रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करेगा, इस पर रूस भी चिंतित है। साथ ही लगातार अमेरिका

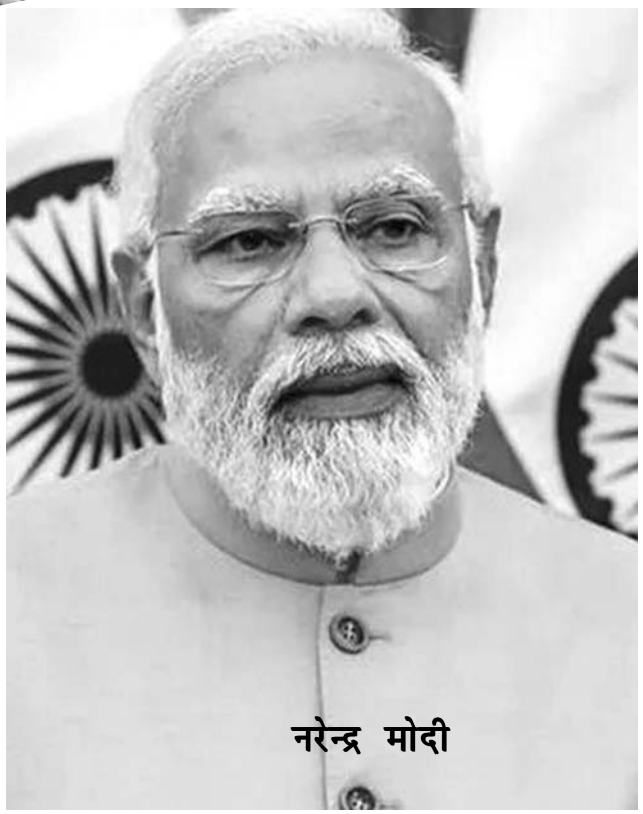

नरेन्द्र मोदी

का और देशों का प्रतिबंध हर स्तर पर आफत में डाल रहा है। रूस के आंतरिक माहौल में भी इसका असर नजर आने लगा है। रूसी लोग इस लड़ाई के त्रासदी के खिलाफ आवाज भी उठाने लगे हैं। इस बात का पुतिन साहब को भी समझ आ रहा है, पर दोनो देशों को इस पर गंभीरता से सोच पर निर्णय की आवश्यकता है, जिससे जल्द समाधान का मार्ग प्रशस्त हो और दोनो के टकराव का अंत हो। साथ ही विश्व के अन्य देशों को भी इस विवाद को समाप्त हेतु ईमानदारी से विचार करना ही होगा, क्योंकि इस लड़ाई का दूरगामी परिणाम भविष्य में जरूर होगा। आज यूएनओ के हर मंच को इस विवाद पर सख्त एवं सतर्क होकर मानवीय आधार पर भी निर्णय लेने होंगे, नहीं तो आने वाले समय में इसका परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुखद होगा, जिसका पूरा विश्व को नुकसान झेलने होंगे। अब तो नाटो में भी आपसी विवाद एवं यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की का नाटो के बाबत गुस्सा सामने आने लगा है। इन्हे भी सच की जानकारी हो रही है की यूक्रेन एक मोहरा के तौर पर बनाने की चाल ही थी। हालांकि विश्व में अब रूस के हमले के विरोध में आवाजे उठने लगी है पर केवल आत्म-विश्वास से ही यूक्रेन, रूस का सामना जरूर कर रहा है पर कब तक कर पायेगा, यह कहना मुश्किल है। भारत भी इस युद्ध के समाधान के लिए लगातार हर मंच से बातचीत द्वारा करने की प्रयासों पर कार्यरत्त है। हमारे प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पर यूक्रेन एवं रूस के राष्ट्रपति से कई बार वार्ता टेलीफोन के माध्यम से किया है और इसी क्रम में यूक्रेन में फंसे लोगों को, जिसमें भारतीय विद्यार्थी जो मेडिकल के लिए अध्ययनरत्त थे, उनके निकासी के लिए गंगा ऑपरेशन के तहत अभियान पर भी दोनो देश से गहन चर्चा की। जिसके परिणामस्वरूप हजारों की संख्या में भारत में वापसी हुई, जिससे भारत में लोगों को राहत के साथ देश के सरकार के प्रति गर्व भी महसूस होना भी स्वभाविक है। इस तहद भारत के सम्मानजनक दावे विश्व में उजागर हो रहा है। सुरक्षित निकासी भारत सरकार की प्राथमिकता का निर्देश एवं भारतीयों को वापसी में भारतीय एयर फोर्स का साथ उदाहरणार्थ है। इस ऑपरेशन गंगा के तहत अभियान पर आम लोगों के अंदर देश के प्रति और भी जर्बदस्त विश्वास की भावना और दुनियां में देश के ताकत और महत्व का एहसास भी हुआ। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा बार-बार हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शांति समाधान का आग्रह करना देश के महत्व को दर्शाता है। रूस भी हाल के दिनों में भारत के साथ रूख और नीति पर अपना मित्रवत बयान दिये हैं। मतलब साफ है आज दुनियां भारत के निष्पक्ष सोच पर मुहर लगाता है।

एक बात सर्वविदित है स्वार्थ पर टिका हुआ संबंध कभी भी स्थायी नहीं होता, यही अब इस भयंकर युद्ध में समझ आ रहा है। महाशक्ति अमेरिका और नाटो जैसे देश अब यूक्रेन को उसके हालात पर जमीनी स्तर पर कोई साथ नहीं दे रहा। केवल अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक, सामरिक मदद की बयानबाजी और समर्थन के नाम पर आग में घी डालते भी नजर आ रहे हैं। बमबारी से यूक्रेन पूरी तौर पर तबाही के हालात में है, पलायन जर्बदस्त और किव पर कब्जा की नजदीक। एक बात

और समझ में जरूर आना चाहिए कि यूएनओ भी लगभग निष्क्रीय हालत में है। आने वाले समय में दुनियां के इस पंचायत वाली माननीय संस्था पर विचार जरूर हो, क्योंकि बिगड़े हुए माहौल पर इस संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या दिशा निर्देश हो, इसकी ताकत पर भी प्रश्न जरूर उठेंगे। क्योंकि जो विश्व को उम्मीद होती है, वह मौके पर पूरे करने में सक्षम और निर्देशों में सही निर्णायक भूमिका क्यों नहीं? यूक्रेन और रूस का यह भयंकर युद्ध नकाम कुटनीति का भी नतीजा है। रूस द्वारा शुरू में ही डोनेत्सक एवं लुहांस्क को स्वतंत्र देश और मान्यता, विश्व के लिए सही संदेश नहीं था। यह अंतर्राष्ट्रीय नियम के खिलाफ प्रक्रिया थी। इस पर भी किसी को शक की गुंजाइश नहीं थी पर यूरोप के कई देश अमेरिका एवं नाटो देशों का नजर सोवियत संघ के विखराव के बाद अलग हुए देशों पर थी और अपने साथ लाने का सोच और महाशक्ति बनने के होड़ में यह महाविनाशक युद्ध कब तक जारी रहेगा, यह भविष्य ही बतायेगा। भारत की भी समस्या बढ़ाने वाला यह यूक्रेन संकट जरूर है। इसका असर चाहे वह कुटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक सामरिक स्तर पर हो, इसमें भी कोई शक नहीं, पर भारत का विदेश मंत्रालय और सरकार अपने देश के हित एवं भविष्य के हालातों के मद्देनजर अपने तटस्थ एवं साथ ही साथ पुराने अनुभवों को ध्यान में रखकर शांति समाधान के लिए प्रयासरत्त है। आज भारत के तरफ विश्व की नजर भी है, पर देश अपने आप को नीति और ईमानदार तटस्थ सिद्धांतों पर विश्व पटल के समस्याओं का समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही मानवीय आधार पर हर तरह से जरूरतों के लिहाज से सहायता के भी कार्यों में जुटा हुआ है। हाल के दिनों में फ्रांस, जर्मनी, इजरायल और भारत के तरफ से युद्ध विराम के लिए प्रयास हो रहे हैं। इस युद्ध ने

भयंकर तबाही का हद पार कर चुका है। बड़े-बड़े शहर, रिहायशी इलाके, परमाणु सयंत्र और अस्पताल एवं स्कूलों की भी पूरी तरह से बर्बादी नजर आ रही है। अब जो तस्वीर यूक्रेन से आ रही है, उससे पूरी मानव जाती दहल चुका है। सवाल जीत-हार का नहीं, क्या होगा इस महायुद्ध के घमासान का, अब इस पर कैसे रोक लगे, इस पर केवल सोच की जरूरत है और अहंकार, अतिक्रमण और बहसीपन, यही कारण है इस महायुद्ध के जारी रहने का। जल्द से जल्द युद्ध विराम हो, इस पर गंभीरता से निर्णय लेने के लिए महाशक्तियों एवं संगठनों को निर्णय लेने होंगे।

रूस की न्यूक्लीयर धमकी से पूरे विश्व को खतरा है, यह अमेरिका का कहना है। यूक्रेन के लिए पुतिन बहुत आक्रमक हो गये हैं। वह अपने गुस्से में कुछ भी करने को तैयार हैं और परमाणु हमले की संभावना भी कर सकते हैं। यही कारण है कि यूक्रेन सीमा पर अमेरिकन लड़ाकू विमानों का जमावड़ा, नाटो भी अपने संगठन के मजबूती के एक्शन में है, जो विश्व के जंगी माहौल को और खराब कर सकती है। पर अब जलेस्की लाचार हालात में रूस से हर स्तर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। रूस अपने हक में, जो उसकी सोच है कि अपने समर्थन वाला सत्ता यूक्रेन में स्थापित करने का ख्वाब वह पूरा हो सकता है, जिस तरह से रूसी सैन्य शक्ति का एक्शन जारी है। रूसी हमले में पूरा यूक्रेन मलवे की ढ़ेर हो चुका है। लड़ाई शहरों में जब होती है तो लड़ाई की टैक्टीस में काफी तबदीली करनी होती है। कीव में रूस आतंकियों को भेजने की तैयारी में है। इस तरह का बयान यूक्रेन रक्षा मंत्रालय द्वारा की जा रही है। दूसरे तरफ पुतिन का परमाणु बम के इस्तेमाल पर बार-बार बयान दुनियां को बेवजह आफत में डाल सकता है। बम, बारूद के बाद इस युद्ध में बायो वेपन से भी प्रहार दोनो देशों के द्वारा हो रहे हैं, जो अति शर्मनाक और दुखद है। इस पर जल्द ही गंभीरता से नीतिगत निर्णय हो और जल्द लड़ाई पर रोक लगे।

इस युद्ध में हमारे देश के एक युवा छात्र नवीन जो खरकीव में मेडिसिन के लिए गये थे, पर गोलाबारी के दौरान उनकी मौत हो गई, जो देश के लिए दुखद घटना रही। राहत की बात है कि भारत सरकार को ऑपरेशन गंगा अभियान से लगभग छात्रों एवं भारतीयों को वापसी हो रही है। विदेशों में पढ़ने वाले हमारे देश के छात्र-छात्राओं की वापसी इस महायुद्ध में जर्बदस्त समस्या सा हो गया था, पर दोनो देशों के साथ संवाद एवं अभिजन से इसमें सफलता प्राप्त हुई। भारत के समक्ष आज इस महायुद्ध के समय संतुलन साधने की चुनौती है और कोई भी कदम देश के भविष्य के कुटनीतिक, राजनीतिक एवं व्यापारिक, सामरिक पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसलिए पुराने अनुभव अपने साथ के मित्रवत व्यवहारों और समर्थन का ध्यान रखकर ही विश्व के मंच पर आगे बढ़ने होंगे क्योंकि दुनियां इस महायुद्ध में दो भागों में बढ़ चुका है और भारत भी पूरी तौरपर इस बाबत सजग है और जरूरी भी है। भारत की अपनी समस्याएं, जरूरतें और सुरक्षा की हालात है और विश्व पटल पर हर देश से अलग-अलग स्तर पर कई समझौते भी है और विश्व के नजर में भारत एक निष्पक्ष एवं निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है तो भारत को अपने हर निर्णय को बहुत सोची समझी निर्णय से स्थापित करने का समय है यही आज हमारा भारत करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यूक्रेन के साथ विश्व के अधिकतर देशों की सहानुभूति है पर दोनो पक्षों के साथ मिल बैठकर वार्ता से लड़ाई एवं इसके राजनीतिक, कुटनीतिक समाधान पूरी तौर पर हो। इस पर यूएनओ का सतर्क भूमिका की भी जरूरत है। तीसरे विश्वयुद्ध को टालने के लिए साथ ही परमाणु लड़ाई का माहौल ना बने, इस पर सात ढ़ंग से आज विचार एवं समझ की जरूरत है, एक बात साफ है कि यूक्रेन और रूस के महायुद्ध में कुछ संगठन और देशों का अपना स्वार्थ भी निहीत है। आग में घी डालने वाले एक्शन, बयानो पर अंकुश आज की जरूरत है। इस महायुद्ध में पूरे विश्व को इसके दुष्परिणाम को भुगतना पड़ेगा, चाहे वह व्यापारिक हो या सामरिक, भारत भी इस हालत पर बड़े दूरदर्शी लक्ष्य पर कार्यरत्त है। विशेषकर हमारा विदेश मंत्रालय जो किसी भी आपातकालिन परिस्थिति में भारत के हित और सुरक्षा पर सतर्क है, क्योंकि लड़ाई का अंत केवल विनाशकारी ही होता है, इससे किसी भी पक्ष को फायदा नहीं होता और इससे दूरी बनाना हर देश, संगठन को आज की जरूरत है, क्योंकि युद्ध के घातक मंसूबे विश्व के बेहतरी को बाधा पहुंचाती है। राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता ना खराब होने पाये, यह सुनिश्चित करने का समय है और इसके लिए विश्व के सभी देशों को एक मत से सहमति बनाने की जरूरत भी और इसी के विश्व में सही और आपसी मेल भाव का माहौल बनाने में कामयाबी प्राप्त हो पायेगी। ●

(लेखक बी.एस.एफ. के पूर्व अधिकारी हैं।)

SHAMEFUL! Woman sexually harassed at Bhagoria mela in MP

A video of a young woman being sexually harassed in public by two youths during a Bhagoria fair at Walpur village within this tribal-dominated district's Sondwa Police Station limits is the subject of a police investigation and has drawn condemnation from Madhya Pradesh's principal-opposition Congress. In the video, the girl was heard screaming as men molested her one by one, and onlookers were seen recording videos with their phones instead of helping the girl. "The incident occurred on Saturday and a complaint was lodged by the Jai Adivasi Yuva Shakti Sangathan's Mukesh Rawat. We are questioning a youngster who made the video viral in social media," Town Inspector SS Baghel said on Sunday.

हिजाब के बाद अब हलाल पर बवाल

कर्नाटक में एक हिंदू दक्षिणपंथी गुट हलाल मांस की खरीद के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रहा है। हिंदू जनजागृति समिति ने कहा कि इस्लामी प्रथाओं के तहत काटे जाने वाले मांस को अन्य देवताओं को नहीं चढ़ाया जा सकता है। संगठन के प्रवक्ता मोहन गौड़ा ने कहा, 'उगादी के दौरान, मांस की बहुत खरीद होती है और हम हलाल मांस के खिलाफ एक अभियान शुरू कर रहे हैं। इस्लाम के अनुसार, हलाल मांस पहले अल्लाह को चढ़ाया जाता है और इसे हिंदू देवताओं को नहीं चढ़ाया जा सकता है। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर दक्षिणी राज्य में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है। गौड़ा ने कहा, 'हर बार जब मुसलमान किसी जानवर को काटते हैं, तो उसका चेहरा मक्का की ओर कर दिया जाता है और नमाज पढ़ी जाती है। एक ही मांस हिंदू देवताओं को नहीं चढ़ाया जा सकता है। हिंदू धर्म में हम जानवर को प्रताड़ित करने में विश्वास नहीं करते हैं और इसे (बिजली के) झटके से मार दिया जाता है' इसी संगठन ने राज्य के उडुपी में मंदिर के समारोह में गैर-हिंदू कारोबारियों और दुकानदारों को एंट्री नहीं देने की मांग की है। अब यह मांग राज्य के अन्य हिस्सों में स्थित मंदिरों में आयोजित होने वाले वार्षिक मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी की जाने लगी है। शुरुआत उडुपी जिले में आयोजित वार्षिक कौप मरीगुड़ी उत्सव से हुई जहां पर बैनर लगाए गए, जिसपर लिखा गया था कि गैर-हिंदू दुकानदारों और कारोबारियों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरह के बैनर अब पद्बिदरी मंदिर उत्सव और दक्षिण कन्नड जिले के कुछ मंदिरों में भी लगाए गए हैं। हिंदू कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह कदम मुस्लिमों द्वारा हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आए फैसले के खिलाफ बंद का समर्थन करने का जवाब है। उन्होंने कहा कि यह उनका देश के कानून और भारत की न्याय प्रणाली के प्रति असम्मान दिखाता है। सूत्रों ने बताया कि हिंदू मंदिरों के कार्यक्रमों में गैर-हिंदू कारोबारियों को रोकने के लिए इसी तरह के ज्ञापन मांड्या, शिमोगा, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु, हासन और अन्य स्थानों पर दिए गए हैं और बैनर लगाए गए हैं।

13-yr-old Jiya Rai with autism swims 29 km across Palk Strait in record 13 hours!

Jiya Rai, daughter of a senior Indian Navy sailor, brought laurels to the country by swimming across the Palk Strait, from Talaimannar, Sri Lanka to Dhanuskodi in India, a distance of 29 km in 13 hours and 10 minutes on March 20. "A child with Autism Spectrum Disorder, she achieved the feat at the age of 13 years and 10 months, becoming the youngest and fastest female swimmer in the world to swim across the Palk Strait," the Defence Ministry said.

The record was earlier held by Bula Chowdhary who swam the distance in 13 hours 52 minutes in 2004. The event was conducted by the Para Swimming Federation of India (PSFI) with cooperation from many agencies including the Swimming Federation of India, Sports Development Authority, Tamil Nadu and the Autism Society of India. The Goa Shipyard Limited provided the swimmer financial sponsorship for the event. During the event, the Sri Lankan Navy provided search and rescue cover in Sri Lankan waters while the Indian Navy and Indian Coast Guard provided similar support in Indian waters, the Defence Ministry said. Vice Admiral Ajendra Bahadur Singh, Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, congratulated Ms. Jiya Rai and her parents on the stupendous achievement. Jiya Rai, a recipient of many awards including the prestigious Pradhan Mantri Rashtriya Bal Purashkar - 2022, is on a mission to swim in all oceans of the world.

पीएम मोदी के साथ मॉरिसन की मीटिंग से पहले ऑस्ट्रेलिया ने 29 बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटाई

भगवान शिव, भगवान विष्णु और जैन परंपरा आदि से संबद्ध 29 पुरावशेषों को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वापस लौटा दिया है, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण किया। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। ये पुरावशेष अलग-अलग समय अवधि के हैं, जिसमें से कुछ तो 9-10 शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। सूत्रों ने बताया कि एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 29 पुरावशेषों को भारत को वापस किया है। ये पुरावशेष छह श्रेणियों, 'शिव और उनके शिष्यों', 'शक्ति की पूजा', 'भगवान विष्णु और उनके रूप', जैन परंपरा, चित्र और सजावटी वस्तुओं से नाता रखते हैं। सूत्रों ने बताया कि ये मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे बलुआ पत्थर, संगमरमर, कांस्य, पीतल से बनी मूर्तियां और कागज पर बनी चित्रकारी (पेंटिंग) हैं। ये प्राचीन वस्तुएं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से आए पुरावशेषों का निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के साथ एक ऑनलाइन वार्ता करेंगे।

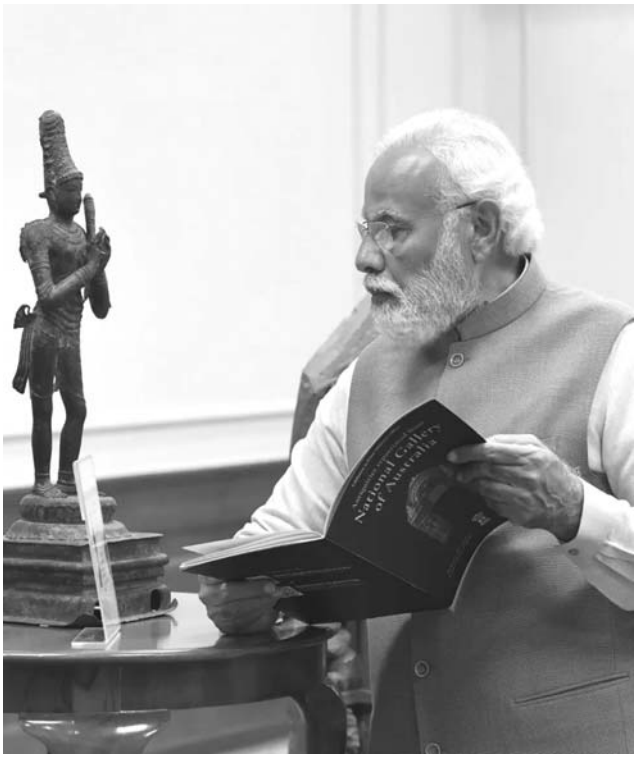

रोजगार का पर्याय है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज

● ललन कुमार प्रसाद

यदि रिहायशी भवन न हो तो लोग कहां रहेंगे; यदि व्यवसायिक केन्द्र न हो तो लोग सामानों की खरीद-बिक्री कहां करेंगे; यदि स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और लेबोरेटरी न हो तो बच्चों से लेकर बुढ़ों तक लोग पठन-पाठन कहां करेंगे; यदि अस्पताल और दवा की दुकाने न हो तो मरीज अपना इलाज कहां करवायेंगे और दवा कहां से खरीदेंगे; बस अड्डे न हो तो बसे कहां ठहरेंगी, क्योंकि बसों को ठहरने का स्थान निर्धारित होते हैं। यदि बसे, बस अड्डों पर नहीं ठहरेंगी तो लोग बसों में कहां पर चढ़ेंगे और बसों से कहां पर उतरेंगे; यदि प्लेटफॉर्म सहित रेलवे स्टेशन न हो तो ट्रेनें कहां ठहरेगी और यात्री ट्रेनों पर कहां चढ़ेंगे तथा ट्रेनों से कहां उतरेंगे; यदि हवाई पट्टी सहित हवाई अड्डे न हो तो हवाई जहाज कहां से उड़ान भरेंगे और कहां उतरेंगे; यदि हवाई अड्डे न हो तो लोग कहां से हवाई जहाज पर चढ़ेंगे और कहां पर हवाई जहाज से उतरेंगे। उपरोक्त सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए भांति-भांति के भवन, सड़क, पुल-पुलिया, रेलवे ट्रैक, सुरंग आदि के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने और विस्तार करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की स्थापना करनी होगी और इन्हें विकसित करनी होगी, जो भवनों के फाउंडेशन से लेकर सुपर स्ट्रक्चर तक का नक्शा तैयार करना और उनका निर्माण करने से ही संभव होगा। यह तभी संभव है, जब सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर और मजदूर सहित 150 करोड़ से ज्यादा लोग उपरोक्त सभी भौतिक संरचनाओं के निर्माण हेतु कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इतना ही नहीं दुनियां भर में सैकड़ों-करोड़ के भवनों के मरम्मत तथा रख-रखाव (मेंटेनेंस) का काम सालोभर चलता रहता है। जिधर नजर दौड़ाइये, उधर हर जगह कंस्ट्रक्शन के कार्य दिखते ही रहते हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होना चाहिए कि नौकरी और रोजगार का पर्याय है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज।

✯ क्या है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज? :- दुनियांभर में औद्योगिकरण व शहरीकरण स्थापित करने, विस्तार करने अैर नवीनीकरण करने को लेकर विभिन्न प्रकार की भौतिक संरचनाओं के निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव के कार्य सालोभर दिन-रात चलते ही रहते हैं। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर यानि बुनियादी ढ़ांचा खड़ा करने को औद्योगीकरण व शहरीकरण का विस्तार तथा नवीनीकरण कहा जाता है। मानव जीवन को सुख-सुविधा और सहुलियतें उपलब्ध कराये जाने के लिए यह आवश्यक आवश्यकता है। इसलिए जरूरी इंफ्रास्टक्चर का होना हर समाज और देश के विकास एवं समृद्धि की रीढ़ मानी जाती है। सड़क, पुल-पुलिया, रेलवे ट्रैक, हवाई पट्टी और जरूरत के मुताबिक विभिन्न आकार एवं आकृति के भवनों को उचित जगह पर उचित तरह का बनाया जाना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के तहत आता है। इस काम को सिविल पर्सनल, आर्किटेक्ट पर्सनल, हेल्थ व एनवायरमेंटल पर्सनल और सेफ्टी पर्सनल के संयुक्त दिशा निर्देश और देखरेख में अंजाम तक पहुचाया जाता है। विभिन्न प्रकार की भौतिक रचनाओं को जिस किसी भी उद्देश्य के लिए खड़ा किया जाता है, उसके लिए निम्नलिखित बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए:-

☞ स्थान विशेष की भगौलिक परिस्थिति और कार्य के स्वभाव के अनुसार उपयुक्त स्थान का चुनाव करना चाहिए।

☞ जरूरत के मुताबिक विभिन्न प्रकार की भौतिक संरचनाओं को खड़ा करने के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लेकिन बेहतर तो यही होगा कि पर्याप्त जमीन से भी कुछ अधिक जमीन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर भविष्य में औद्योगिकरण का विस्तार करने में सहुलियत हो। मसलन सुगर फैक्ट्री। सुगर फैक्ट्री का मुख्य उत्पाद चीनी है लेकिन चीनी का उत्पादन करने में बाईप्रोडक्ट के रूप में खोई (सिठ्ठी) प्राप्त होता है, जो कागज निर्माण हेतु बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। बाईप्रोडक्ट के रूप में छोहा (मोलैसिस) प्राप्त होता है, जो अल्कोहल प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा कच्चा माल है। बाईप्रोडक्ट के रूप में प्रेसमड प्राप्त होता है, जो अम्लीय मिट्टी के लिए उत्तम खाद है।

☞ उद्योग विशेष के लिए भौतिक संरचना के निर्माण हेतु जिस समान का उत्पादन करना चाहते हैं, उसके लिए कच्चा माल प्रचूरता में आसपास ही होना चाहिए, जिससे की कच्चे माल की ढुलाई में खर्चा और समय दोनो का ही बचत हो।

☞ कंपनी के पास उपलब्ध पूंजी और संसाधनों को ध्यान में रखकर ही भौतिक संरचना खड़ा करने के छोटे-बड़े आकार का निर्धारण करना चाहिए, जिससे कि पूंजि को लेकर भौतिक संरचना को स्थापित करने का कार्य बाधित न हो, रूके नहीं।

☞ जरूरत के मुताबिक पर्याप्त संख्या में विभिन्न श्रेणियों के इंजीनियर, तकनीशियन और कामगारों को बहाल करना चाहिए, जिससे कि भौतिक संरचना का निर्माण बगैर किसी बाधा के सुचारू रूप से चलता रहे।

☞ भौतिक संरचना के निर्माण हेतु ऐसे वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना चाहिए, जिससे कि सुरक्षित रूप से निर्माण के कार्य को आसानी से पूरा किया जा सके।

☞ भौतिक संरचना के निर्माण हेतु नये कामगारों को काम पर लगाने के पहले कार्य विशेष के अनुसार उपयुक्त प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि कार्य को करने के दौरान दुर्घटना घटने की संभावना

न रहे।

☞ इस बात की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए कि भौतिक संरचना को खड़ा करने के दरम्यान कोई मजदूर घायल न हो, अपंग न हो और मरे नहीं।

☞ इस बात की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए कि हर दिन काम शुरू करने के पहले सभी कामगारों के लिए उनके समक्ष मौजूद खतरे से सुरक्षा हेतु खतरा के स्वभाव के अनुसार पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) हो, जिससे कि उसे पहनकर कामगार काम प्रारंभ करे।

☞ इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि उत्पादन के लिए तैयार भौतिक संरचना ऐसे उपकरणों से सुसज्जित हो, जिससे कि पर्यावरण कम से कम प्रदूषित हो और यदि न हो तो अतिउत्तम। अर्थात् पर्यावरण के संरक्षण का भरपूर ख्याल रखा जाना चाहिए। मसलन चिमनी के अंदर शूट प्रेसिपिटेटर उपकरण लगाये जाने चाहिए, जिससे कि कालिख के कण कम से कम पर्यावरण में उत्सर्जित हो। उत्पाद के उत्पादन के दौरान उत्पन्न कॉर्बन डाईऑक्साइड गैस और सल्फर डाईऑक्साइड गैस को स्क्रबर से गुजारा जाना चाहिए। जिससे कि 90% गैसें चूना जल से प्रतिक्रिया कर चूना जल में ही रह जाये और शेष 10% गैस पर्यावरण में उत्सर्जित हो।

☞ उद्योगों के लिए भौतिक संरचना के निर्माण हेतु इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि स्थान विशेष से उत्पादों के ट्रांसपोटेशन की दृष्टि से अधिकाधिक सुविधाजनक हो। अर्थात् औद्योगिक शहर सड़क, रेल, हवा (एयरपोर्ट) और पानी (बंदरगाह) से जुड़ा हो, जिससे कि उत्पादों का ट्रांसपोटेशन आसानी से शीघ्रतापूर्वक किया जा सके।

☞ भौतिक संरचना के निर्माण का कार्य शुरू करने से पहले कार्य स्थली (वर्क प्लेस) का बैरिकेशन करा देना चाहिए, जिससे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या पशु दुर्घटना

का शिकार न हो तथा कामगार बाहरी लोगों के मौजूदगी के चलते, काम करने के दौरान बाधा महसूस न करे।

☞ भौतिक संरचना आपातकालीन द्वारा (इमरजेंसी एग्जिट) से युक्त होना चाहिए, जिससे कि आपातकालिन अवस्था में कामगार अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल जाये।

☞ भौतिक संरचना उचित स्थान पर उचित तरह के तथा उचित क्षमता के अग्निशामक यंत्र से सुसज्जित हो।

☞ भौतिक संरचना उचित जगह पर उचित प्रकार के फायर डिटेक्टर जैसे स्मोक डिटेक्टर, फ्लैम डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर से सुसज्जित हो, जिससे कि प्रारंभिक अवस्था में ही बगैर किसी विलंब के आग लगने का पता चल जाये।

☞ प्रत्येक भौतिक संरचना, समुचित कम्युनिकेशन सिस्टम से सुसज्जित होना चाहिए।

☞ भवन निर्माण के दौरान ऊँचाई पर काम करने के लिए जो अस्थायी मचान (स्काफोल्ड) बनाया जाता है। उसे फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम से सुसज्जित किया जाना चाहिए, जिससे कि ऊँचाई पर काम करने वाला कोई भी कामगार नीचे जमीन पर न गिरे। ऐसा इसलिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में सर्वाधिक मौतें ऊँचाई से जमीन पर गिरने से होती है। यही कारण है कि मचान की सतह से उसके किनारे पर

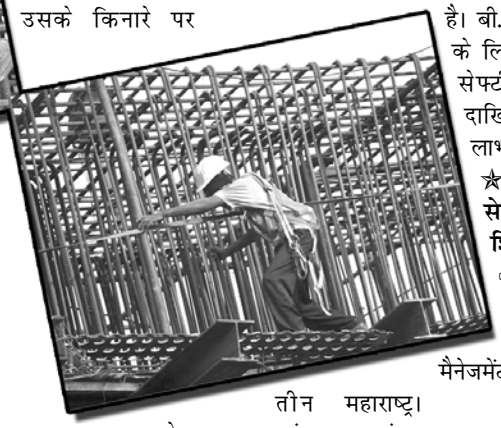

तीन तरफ से एक फुट 9 इंच की ऊँचाई पर मिडरेल और तीन फीट की ऊँचाई पर गर्डरेल लगाया जाना चाहिए। ऊँचाई पर काम करने वालों को सामान्य पीपीई जैसे सेफ्टी शूट, सेफ्टी हेलमेट आदि के अलावा विशेष प्रकार के पीपीई, जैसे-सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी हारनेस अवश्य पहनना चाहिए। जरूरत पड़ने पर सेफ्टी नेट का भी इस्तेमाल करना चाहिए।

☞ ऊँचाई पर काम करने वाले मजदूर को भर्टिगो यानि चक्कर आने या माथा घूमने की फोबिया से ग्रसित नहीं होना चाहिए।

✯ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट में दाखिला पाने हेतु योग्यता :- वैसे तो इंटर पास स्टूडेण्ट्स भी कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन बेहतर तो यही होता है कि स्टूडेण्ट्स इंजीनियरिंग के किसी भी डिसीप्लीन में या आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में बी.टेक किया हो। बी.टेक स्टूडेण्ट्स की सैलेरी 55 से 60 हजार रूपये तक प्रतिमाह से प्रारंभ होती है, जो बहुत ही तेजी से बढ़ती ही जाती है। बी.एससी. स्टूडेण्ट्स के लिए भी कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट में दाखिला लेना बहुत लाभदायक होता है।

✯ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट के शिक्षण संस्थान :-

☞ रियल स्टेट एण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट, पूणे, महाराष्ट्र।

☞ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट, पूणे, महाराष्ट्र।

उपरोक्त दोनो शिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा की पढ़ायी करायी जाती है।

☞ पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ फायर एण्ड सेफ्टी मैनेजमेंट, एग्जिवीशन रोड, पटना, बिहार।

इस सेफ्टी इंस्टीच्यूट मैनेजमेंट में एक वर्षीय डिप्लोमा व पीजी डिप्लोमा की पढ़ाई करायी जाती है। इस इंस्टीच्यूट का लेबोरेटरी देश के सभी सेफ्टी मैनेजमेंट इंस्टीच्यूटों में सबसे बड़ा है, इसलिए यहां पढ़ने वाले स्टूडेण्ट्स देश के अन्य सेफ्टी मैनेजमेंट इंस्ट्रीच्यूटों के मुकाबले ज्यादा लाभान्वित होते हैं।

●

(लेखक फायर एण्ड सेफ्टी विशेषज्ञ हैं।)
मो०:- 9334107607
वेबसाईट www.psfsm.in

बाबा शिवानंद
जिनकी विनम्रता ने जीत लिया देश का दिल

इन दिनों सोशल मीडिया में बाबा शिवानंद के बारे में जमकर चर्चा हो रही है। बाबा शिवानंद तब सुर्खियों में आए जब पद्म सम्मान के दौरान उन्होंने नंदीवत योग की मुद्रा में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति कोविंद के सामने प्रणाम किया। उनकी यह विनम्रता देखकर पूरा देश भावुक हो उठा। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी उनका जिक्र किया। आइए जानते हैं कौन हैं 126 साल के बाबा शिवानंद।

बाबा शिवानंद का जन्म 8 अगस्त 1896 को अविभाजित बंगाल के श्रीहट्ट जिले के ग्राम हरिपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब यह स्थान बांग्लादेश में है। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि बाबा के माता-पिता भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। चार साल की उम्र में माता-पिता ने बेहतर भविष्य के लिए उन्हें नवद्वीप निवासी बाबा ओंकारनंद गोस्वामी को समर्पित कर दिया। शिवानंद 6 साल के थे, तभी उनके माता-पिता और बहन की भूख के चलते निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने गुरु के सानिध्य में आध्यात्म की दीक्षा लेनी शुरू की।

अपने जीवन के 126 साल को पार कर चुके बाबा शिवानंद 6 साल की आयु से संयमित दिनचर्या जी रहे हैं। वे बेहद अनुशासित हैं। बाबा सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। स्नान-ध्यान के बाद रोजाना एक घंटे योग करते हैं। भोजन में न के बराबर नमक और उबले हुए आलू, दाल का ही सेवन करते हैं। वे फल और दूध का भी सेवन नहीं लेते। बता दें कि बाबा ने विवाह नहीं किया है। उनके मुताबिक, ईश्वर की कृपा से उनको कोई बीमारी और तनाव नहीं है। बाबा शिवानंद की मानें तो वे कभी स्कूल नहीं गए, जो कुछ सीखा वह अपने गुरु से ही। उन्हें अंग्रेजी का भी ज्ञान है। उनके आधार कार्ड और पासपोर्ट में उनकी जन्म तिथि 8 अगस्त 1896 दर्ज है। वाराणसी के दुर्गाकुंड इलाके में स्थित आश्रम में शिवानंद बाबा का कमरा तीसरी मंजिल पर है। शिष्यों के मुताबिक वे दिन भर में तीन से चार बार सीढ़ियों से चढ़ते और उतरते हैं।

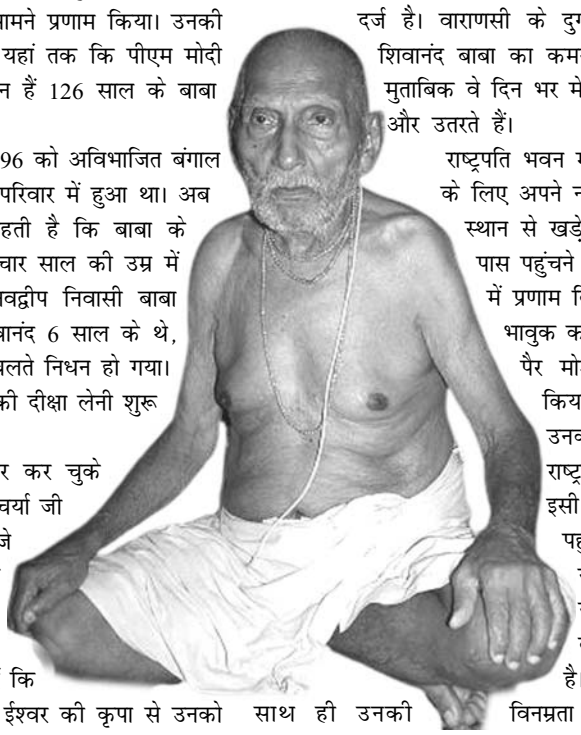

राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद्म सम्मान के लिए अपने नाम की घोषणा सुनने के बाद अपने स्थान से खड़े हुए बाबा शिवानंद ने राष्ट्रपति के पास पहुंचने तक तीन बार नंदीवत योग की मुद्रा में प्रणाम किया, उनकी इस विनम्रता ने सबको भावुक कर दिया। पहले पीएम के सामने दोनों पैर मोड़कर हाथों को आगे कर प्रणाम किया तो पीएम मोदी ने भी झुककर उनका अभिवादन किया। इसके बाद राष्ट्रपति के सामने पहुंचने पर उन्होंने इसी मुद्रा में प्रणाम किया और पास पहुंचने के बाद फिर झुके तो राष्ट्रपति ने उन्हें आगे बढ़कर सहारा दिया। यह वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई बाबा की विनम्रता से अभिभूत है। लोग उनकी और उनकी सेहत के साथ ही उनकी विनम्रता की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

'Hank the Tank' bear that breaks into homes, steals food in California

A massive bear 'Hank the Tank' has been listed in California police's 'Wanted List' for breaking into dozens of homes since last summer. According to BBC, the bear burglar weighing 227 kg, who appears to have skipped hibernation in winter due to a constant food supply, had hungrily barging his way into locked and occupied homes in Lake Tahoe neighbourhood.

California Department of Fish and Wildlife spokesman Peter Tira said, "It's learned to use its size and strength to force its way into homes. It'll barge through garage doors, it'll barge through front doors. It'll go through windows." According to BBC, officials have received more than 150 calls about Hank and he has broken into nearly 40 homes, sometimes causing severe damage, in just the last six months. South Lake Tahoe Police Department said the bear, also known as "King Henry" is "readily identifiable due to [his] exceptionally large size and dark coat with a lighter muzzle". BBC quoted authorities as saying that euthanisation may be necessary because the wild animal has grown so comfortable around humans. However, the wildlife groups have urged for his relocation to a sanctuary.

महिलाओं को सशक्तिकरण सम्मान एवं छात्राओं को पुरस्कार से नवाजा गया

महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के फील्ड आउटरीच ब्यूरो, छपरा द्वारा हाजीपुर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय, मनुआं में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर वैशाली की जिला परिषद उपाध्यक्ष सुंदर माला, हाजीपुर की प्रखंड प्रमुख जयललिता देवी, आईसीडीएस हाजीपुर की सीडीपीओ ओनम शामिल हुईं।

उद्घाटन सत्र कार्यक्रम से पूर्व एफओबी, छपरा एवं आईसीडीएस हाजीपुर द्वारा महिला दिवस पर जागरूकता रैली निकली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं, किशोरियां, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाएं एवं स्कूली छात्राएं शामिल हुईं। स्वागत संबोधन एवं विषय प्रवेश करते हुए कार्यक्रम के आयोजक एवं एफओबी, छपरा के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी सह आरओबी, पटना के कार्यक्रम प्रमुख पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस खास दिन को एक पर्व के रूप में मनाने का उद्देश्य समाज में महिलाओं की भूमिका, योगदान और उनके हौसलों को याद करना है। यह दिन उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का है, उन्हें सलाम करने का है। उन्होंने महात्मा गांधी के संदेशों को कोट करते हुए कहा कि जब एक आदमी को पढ़ाएंगे तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होगा, लेकिन जब एक स्त्री को पढ़ाएंगे तो पूरा परिवार शिक्षित होता है।

वैशाली की जिला परिषद उपाध्यक्ष सुंदर माला ने कहा कि समाज में नारियों को बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य नारियों के अधिकारों और उनके हक को लेकर जश्न मनाने का है। उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने में उन्हें सहयोग करना चाहिए। इससे न केवल महिलाएं सशक्त बनेगी बल्कि देश भी मजबूत बनेगा। हाजीपुर की प्रखंड प्रमुख जय ललिता देवी ने कहा कि हम जो शिक्षा लड़कों को देना चाहते हैं, उसी प्रकार हमें समान शिक्षा लड़कियों को भी देना चाहिए। आज महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिए जाने से महिलाएं सशक्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि

किशोरियों और छात्राओं को पढ़ाई-लिखाई पर अत्यधिक जोर देना चाहिए। यह उनके सशक्तिकरण का मजबूत हथियार है। जब बच्चियां मजबूत और सशक्त बनेगी तब राज्य आगे बढ़ेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। हाजीपुर की सीडीपीओ ओनम ने कहा कि यह दिन उन महिलाओं को सम्मान करने का है, जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक व खेलकूद में अपनी महती भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जुनून और लगन से किशोरियां व छात्राएं कुछ भी हासिल कर सकती हैं, बस उन्हें मन की सोच बदलने और अपने दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर वे शिक्षा को लेकर आगे बढ़ती हैं, तो बहुत नाम रोशन करेंगी। उन्होंने छात्राओं से अपील की कि वे कभी भी पढ़ाई ना छोड़े और साथ ही वह अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षित करें। अपने अंदर लगन और जुनून पैदा करें।

विद्यालय के प्राचार्य अवधेश कुमार ने कहा की महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। कई बार में वे शिक्षा और जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों से

वंचित रह जाती हैं। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे महिलाएं खुद को सशक्त कर सकती हैं। एफओबी, छपरा के सहायक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी सर्वजीत सिंह ने कहा कि महिलाओं का योगदान समाज के हर क्षेत्र में बराबर रहा है। हमें कोविड के उस दौर को भी याद करना होगा, जब अस्पतालों में महिला स्वास्थ्यकर्मी दिन-रात अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा रही थीं। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज की परिकल्पना महिलाओं के बिना संभव नहीं है।

☞ **महिलाओं को सशक्तिकरण सम्मान एवं छात्राओं को पुस्कार से नवाजा गया :-** कार्यक्रम के अंत में विभाग द्वारा विभिन्न वर्ग की सशक्त महिलाओं को मंच से महिला सशक्तिकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन

पूर्व विद्यालय प्रांगण में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता की विजेता टीम की कप्तान मुस्कान को तथा उपविजेता टीम की कप्तान सजल सिंधु को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। इसी प्रकार रस्सी कूद प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहीं क्रमशः सजल सिंधु, प्रिती कुमारी एवं नंदनी कुमारी को भी विशिष्ट अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहीं क्रमशः सलिल गंगा, जया कुमारी और सुरभी कुमारी को भी पुरस्कृत किया गया।

☞ **जादूगर ने मोहा सभी का मन :-** मंत्रालय के पंजीकृत जादूगर ओ पी सरकार ने मंच से जादू का शो दिखाया। महिलाएं, किशोरियां, छात्राएं एवं आम नागरिकों ने जादू के शो का खूब लुत्फ उठाया। जादू के तरह-तरह के कारनामें देख लोगों ने खूब तालियां बजाई।

कार्यक्रम का संचालन युवा सोशल मोबिलाइजर सजल सिंधु ने किया। कार्यक्रम स्थल पर आईसीडीएस, हाजीपुर की पर्यवेक्षिका श्वेता कुमारी, आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं एवं बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं एवं ग्रामीण मौजूद थे।

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

सहकारिता के रास्ते ग्रामीण भारत में विकास को बढ़ावा

● हेमा यादव
(निदेशक, वैमनिकोम)

वर्ष 1904 में भारत में पहला सहकारिता कानून लागू होने के बाद से भारतीय सहकारी संगठन अब तेज गति के बदलाव के लिए तैयार हैं। सहकारिता के क्षेत्र में नए प्रतिमानों और सहकारी संगठनों के लिए बजटीय आवंटन के साथ अलग से एक सहकारिता मंत्रालय की मौजूदगी के रूप में इसके बदलते स्वरूप के साथ विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में भारत के सहकारिता आंदोलन में एक नए सिरे से रुचि बढ़ी है। अलग-अलग समय पर, विशेष रूप से नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) तक, बदलाव के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले सहकारी मॉडल ने भारत की विकास योजना की सफलता में अहम योगदान दिया है। गरीबी उन्मूलन, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, सामाजिक एकीकरण और रोजगार सृजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्रम में इसके अंतर्निहित लाभ हुए हैं। सहकारी क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, जिसकी ऋण और गैर-ऋण समितियों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण भारत में व्यापक पहुंच है। भारत की कुल 8.5 लाख सहकारी इकाइयों में से, लगभग 20 प्रतिशत (1.77 लाख इकाइयां) ऋण संबंधी सहकारी समितियां हैं और शेष 80 प्रतिशत गैर-ऋण सहकारी समितियां हैं, जोकि लगभग नब्बे प्रतिशत गांवों को कवर करती हुई मत्स्य, डेयरी, उत्पादक, प्रसंस्करण, उपभोक्ता, औद्योगिक, विपणन, पर्यटन, अस्पताल, आवास, परिवहन, श्रम, खेती, सेवा, पशुधन, बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां आदि जैसी विविध गतिविधियों में शामिल हैं। सदस्यता के संदर्भ में अगर बात करें, तो लगभग दो सौ नब्बे मिलियन किसान सहकारी समितियों में नामांकित हैं। इनमें से 72 प्रतिशत किसान ऋण संबंधी सहकारी समितियों और 28 प्रतिशत किसान गैर- ऋण संबंधी सहकारी समितियों से जुड़े हैं (एनसीयूआई, 2018)।

प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां (पैक्स) देश की अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) से संबंधित निर्माण खंड हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 31 मार्च 2018 तक कुल 6,39,342 गांवों को कवर करते हुए 13.2 करोड़ सदस्यों के साथ देश में कुल 95,238 पैक्स उपलब्ध थे। ये समितियां गांवों में किसानों और निम्न-आय वर्ग के लोगों की वित्तीय सहायता करके उनके वित्तीय सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक अच्छे नेटवर्क और पैक्स जैसे संस्थानों की जरूरत होने के बावजूद, पैक्स के माध्यम से धीमी गति से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) का कहना है कि सहकारी समितियां स्वयं सहायता, आत्म-जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता, हिस्सेदारी और एकजुटता के मूल्यों पर आधारित होती हैं। अपने संस्थापकों की परंपरा में, सहकारी समितियों के सदस्य ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों की देखभाल जैसे नैतिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सहकारिता के मूल सिद्धांत से समझौता किए जाने की वजह से वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओं के वितरण में गिरावट आई है। ऋण चुकता करने के क्रम में अपर्याप्त धन संबंधी चूक, पेशेवर मानव संसाधनों की कमी और तकनीक के धीमे समावेश के परिणामस्वरूप प्रबंधन संबंधी सूचना की खराब प्रणाली, पारदर्शिता, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में शिथिलता, कदाचार की समस्याएं पैदा हुई है जिसके कारण विकास की प्रक्रिया में रुकावट आई है।

☞ **एक बहुउद्देशीय समिति के रूप में पैक्स :-** मेहता समिति

(1937) ने बढ़ते संकट और असंतोष को दूर करने के लिए सहकारी ऋण समितियों को 'बहुउद्देश्यीय' सहकारी समितियों के रूप में पुनर्गठित करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा, आजादी से पहले के काल में, सर मणिलाल नानावटी की अध्यक्षता वाली कृषि ऋण संगठन समिति ने सहकारी समितियों को एक व्यावहारिक व्यावसायिक इकाई बनाने के लिए कृषि वित्त में राजकीय सहायता और सभी सहकारी ऋण समितियों को बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों में बदलने पर जोर दिया था और इस संबंध में सिफारिश की थी। सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स को सिर्फ एक ऋण समिति के बजाय एक ऐसी बहु-धंधी समिति के रूप में प्राथमिकता दी है जोकि ऋण एवं विभिन्न सेवाओं के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य कर सके। पुनरुद्धार की यह प्रक्रिया पैक्स को सेवा संगठनों के रूप में एक नई दिशा देने और कृषि विपणन, बागवानी, खाद्य तेल, उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास, प्राकृतिक खेती आदि से संबंधित कृषि बजट 2022-23 की विभिन्न योजनाओं के साथ एकीकृत करने का भी आह्वान करती है। खरीद, भंडारण एवं वेयरहाउसिंग, प्रसंस्करण, ग्रामीण एवं कृषि संबंधी लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन, बाजार संबंधी परामर्श एवं खुफिया जानकारी आदि जैसी गतिविधियों पर अमल कर पैक्स को बहुउद्देशीय समितियों के रूप में

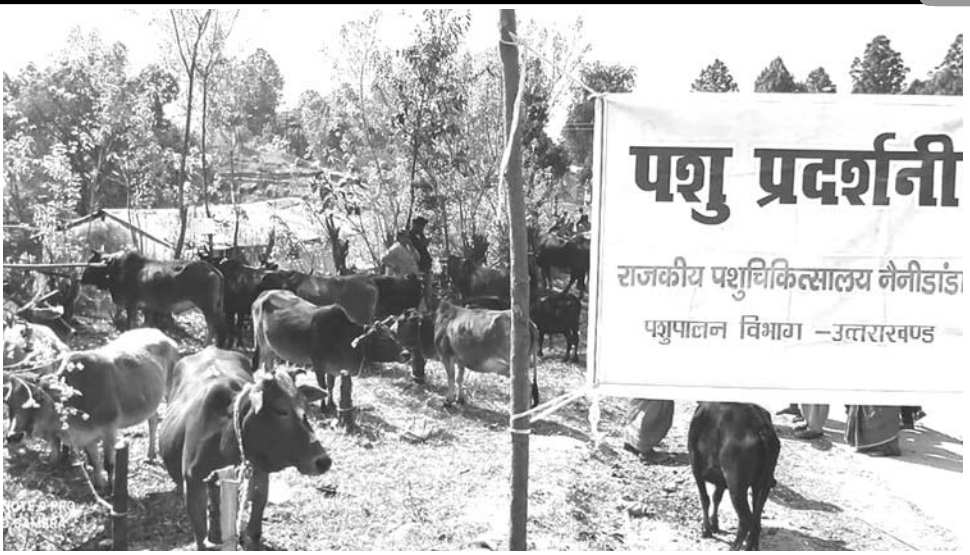

मजबूत किया जाएगा। हालांकि वर्तमान की बाजार एवं प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों के प्रमुख सिद्धांतों के रूप में सदस्यों की आर्थिक भागीदारी और सहकारी समितियों के बीच परस्पर सहयोग की केंद्रीयता बनाए रखने की जरूरत है।

☞ **पैक्स का डिजिटलीकरण :-** पैक्स का डिजिटलीकरण प्रौद्योगिकी को अपनाने और व्यावसायिक दृष्टि से व्यवहारिक बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। केन्द्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण के लिए 350 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा 63000 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने की योजना तैयार की गई है। पैक्स का डिजिटलीकरण कृषि संबंधी कई पहलों के कार्यान्वयन में सहायता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को डिजिटल समावेशिता के माध्यम से पारदर्शी तरीके से ऋण, उर्वरक और बीज प्राप्त हों। पैक्स में प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण किया जाना भी बेहद जरूरी है।

सहकारिता के इस डिजिटल ब्रह्मांड में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी और स्थायी रूप से प्रदर्शन करने के लिए पैक्स द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में विविधता लाना, नवाचार करना, ज्ञान साझा करने में सहयोग करना और उभरती हुई तकनीक का उपयोग किया जाना बेहद जरूरी है। बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन तकनीक जैसे उद्योग 4.0 के विभिन्न पहलू वितरण संबंधी आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता और विश्वास का समावेश करते हैं। मसालों, मत्स्यपालन, काजू और केसर, जोकि सहकारी समितियों के सदस्यों की अच्छी भागीदारी के साथ उच्च मूल्य वाले और निर्यात-उन्मुखी उत्पाद हैं, की आपूर्ति श्रृंखला में ब्लॉकचेन तकनीक का समावेश करने का यह सही समय है। पैक्स के सदस्यों के निरंतर प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना समय की मांग है। पैक्स के डिजिटलीकरण के क्रम में विभिन्न संस्थानों द्वारा केएपी (ज्ञान, दृष्टिकोण व्यवहार) को अपनाए जाने की जरूरत है जोकि प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ-साथ अपेक्षित परिणाम की दिशा में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का समावेश करेगा। सहकारी समितियों को किया गया बजट आवंटन विकास और समृद्धि के संचालक के रूप में सहकारी समितियों की ओर ध्यान केन्द्रित किए जाने को दर्शाता है। नवाचारों, उद्यमशीलता और प्रशिक्षण का लाभ उठाते हुए, यह बजटीय आवंटन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि कैसे पिरामिड के सबसे निचले हिस्से से विकास को ऊपर की ओर ले जाया जाए और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कपड़ा, छोटे एवं मध्यम उद्यमों, ऊर्जा, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों के साथ निरंतर जुड़ाव और एकीकरण को आगे बढ़ाया जाए।

400 साल तक बर्फ में दबे रहे केदारनाथ धाम के रहस्य

● अनिरुद्ध जोशी

भारत के उत्तराखंड राज्य में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर। इस संपूर्ण क्षेत्र को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान छोटा चार धाम में से एक है। केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आओ जानते हैं इस संबंध में 10 रहस्यमयी जानकारी।

☞ **शिवलिंग उत्पत्ति का रहस्य :** पुराण कथा अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदार घाटी में दो पहाड़ हैं- नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। इसी आशय को शिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है।

☞ **पांडव कथा :** कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्गप्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे जो बाद में धरती में समा गए लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पुंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ (नेपाल) कहा जाता है। पुराणों में पंचकेदार

की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है।

☞ **केदारनाथ और पशुपति नाथ मिलकर पूर्ण शिवलिंग बनता है :** केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसे अर्द्धज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। यहां स्थित स्वयंभू शिवलिंग अतिप्राचीन है। यहां के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया था और जीर्णोद्धार आदिशंकराचार्य ने किया था।

☞ **एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर :** केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिरकी सीध में बना हुआ माना जाता है। उक्त दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर (तेलंगाना), श्रीकालाहस्ती मंदिर (आंध्रा), एकम्बरेश्वर मंदिर (तमिलनाडु), अरुणाचल मंदिर (तमिलनाडु), तिलई नटराज मंदिर (चिदंबरम) और रामेश्वरम् (तमिलनाडु) आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

☞ **400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा मंदिर :** वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदिशंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देहत्याग गए आदिशंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णत: सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल, केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लैशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लैशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जलप्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी।

☞ **6 माह तक नहीं बुझता है दीपक :** दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखीमठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ-सफाई मिलती है, जैसी कि छोड़कर गए थे।

☞ **लुप्त हो जाएगा केदारनाथ :** पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में 'भविष्यबद्री' नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा।

☞ **तूफान और बाढ़ में भी रहता है सुरक्षित :** 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जलप्रलय से कई बड़ी-बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गईं, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ, जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई! उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10 हजार लोगों की मौत हो गई थी।

☞ **कैसे बना होगा यह मंदिर अभी भी रहस्य बरकरार :** यह मंदिर कटवां पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी? खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई? पत्थरों को एक-दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

☞ **निरंतर बदलती रहती है यहां की प्रकृति :** केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22 हजार फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21 हजार 600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22 हजार 700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहां- मंघ्दाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहां सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहां कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता।

✯ संगेय एवं असंज्ञेय अपराध किस प्रकार के अपराध होते हैं एवं उनमे मूलभूत रूप से क्या अंतर होता है ?

अपराधों की प्रकृति के अनुसार उन को दो भागों में बांटा गया है प्रथम संगेय अपराध एवं द्वितीय असंगेय अपराध । अपराधों का यह वर्गीकरण उनकी गंभीरता एवं सामान्य प्रकृति के आधार पर किया गया है ऐसे अपराध जो संगीन एवं गंभीर प्रकृति के होते हैं संगेय अपराध कहे जाते हैं एवं जो सामान्य प्रकृति के होते हैं वे असंगेय अपराध समझे जाते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(ग) के अनुसार संगेय अपराध के मामलों से अभिप्राय ऐसे अपराध एवं मामलों से होता है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के अनुसार या उस समय लागू किसी विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अपराध संगेय है या असंगेय यह दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के स्तंभ 4 में दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी मामले की सूचना मिलने पर तुरंत उसका अन्वेषण शुरू कर सकता है जब की धारा 155 के अंतर्गत अपराध के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी उस का अन्वेषण मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश मिलने पर ही कर सकता है दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची दो में अन्य विधियों के विरुद्ध अपराधियों का वर्गीकरण है जिसके अनुसार पुलिस अधिकारी वारंट के बिना केवल उन अपराधों में गिरफ्तारी कर सकता है जिनमें अपराध 3 वर्ष और उससे अधिक कारावास से दडनीय है यदि किसी मामले में एक या अधिक अपराध सगेय हो तो वह संगेय अपराध माना जाता है कोई केस असंगे केवल तभी हो सकता है जब उसकेस में का प्रत्येक अपराध असंगेय अपराध हो। संगेय और असगेय अपराधों में मूल अंतर निम्नलिखित प्रकार से है ।संगेय अपराध गंभीर एवं संगीन प्रकृति के होते हैं जबकि अ संगेय अपराध सामान्य प्रकृति के होते हैं संगेय अपराधों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है जबकिअसगेय मामलों में पुलिस बिना वारंट के मुदालय को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। संगेय मामलों में पुलिस अधिकारी बिना किसी आदेश के अन्वेषण शुरू कर सकता है जबकि असगेय मामलों में बिना आदेश के अन्वेषण नहीं किया जा सकता है संगेय मामलों में कार्यवाही करने के लिए परिवाद की आवश्यकता नहीं होती है जबकि असगेय मामले में कार्यवाही का प्रारंभ परिवाद से होता है।

✯ अजीत कुमार चोरी के इरादे से बबलू कुमार के घर में प्रवेश करता है बबलू कुमार तथा उसके घर के अन्य व्यक्ति अजीत कुमार को घेरकर लाठियों से आक्रमण करते हैं अजीत कुमार अपने जीवन को संकट में पाकर पिस्तौल निकालकर गोली चला देता है जिससे बबलू कुमार की मृत्यु हो जाती है तो क्या अजीत कुमार हत्या का दोषी होगा?

अजीत कुमार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार हत्या का दोषी माना जाएगा , प्रस्तुत समस्या प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है इस समस्या के दो पक्ष हैं पहला अजीत कुमार चोरी करने के आशय से बबलू कुमार के घर प्रवेश करता है इसलिए बबलू कुमार को अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा करने का अधिकार है और इस अधिकार के प्रयोग में वह अपने घर के सदस्यों के साथ अजीत कुमार को घेरकर लाठियों से आक्रमण करता है यहां हो सकता है कि बबलू कुमार को अपने शरीर एवं संपत्ति के प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अधिकार रहा हो किंतु विधि की उपेक्षा उसके पक्ष में नहीं होगा ,दूसरा दिए समस्या में अजीत कुमार केबल चोरी करने के आशय से बबलू कुमार के घर नहीं गया था उसके पास पिस्तौल होना इस बात का साक्षी है कि वह इस तैयारी के साथ बबलू कुमार के घर में चोरी करने गया था कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह उस पिस्तौल का प्रयोग करेगा उसका पूर्व चिंतन था कि वह विरोध किए जाने पर मकान मालिक की हत्या भी कर सकता है इसलिए अजीत कुमार

कानूनी सलाह
शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

अपनी जीवन को संकट से बचाने का लाभ नहीं ले सकता है क्योंकि वह स्वयं बबलू कुमार के घर चोरी करने गया था जो स्वयं में अपराध है, इसलिए अजीत कुमार भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 100 में वर्णित व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है और वह हत्या का दोषी माना जाएगा।

✯ मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट की शैक्षिक महत्व क्या है?

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 291(क) के अंतर्गत इस विषय में उपबंध किया गया है जिसके उपधारा (1) के अनुसार कोई दस्तावेज जो किसी व्यक्ति या संपत्ति की बाबत किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को हस्ताक्षरित शिनाख्त रिपोर्ट होनी आवश्यक है इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी यद्यपि ऐसे मजिस्ट्रेट को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है परंतु जहां ऐसे रिपोर्ट में ऐसे किसी संदिग्ध व्यक्ति या साक्षी का विवरण है जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 21, 32, 33, 155 या धारा 157 में उपबंध लागू होते हैं वहां ऐसा विवरण धारा 37 के अधीन उन धाराओं के उपबंध के अनुसार के सिवाय प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। पुन: उपधारा 2 में उपबंधित किया गया है कि न्यायालय यदि ठीक समझता है तो अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे मजिस्ट्रेट को सम्मन और उक्त रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में परीक्षण कर सकेगा। अत: शिनाख्त रिपोर्ट का शैक्षिक महत्व उपयुक्त के अनुसार सीमित है।

✯ जानिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के बारे में।

आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में भारत की संसद ने पारित किया था। तब से सरकार इस कानून की मदद से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है ताकि यह चीजें उपभोक्ताओं को उचित दाम पर उपलब्ध हो सके। सरकार अगर किसी चीज को आवश्यक वस्तु घोषित कर देती है तो सरकार के पास यह अधिकार आ जाता है कि वह उस पैकेज्ड प्रोडक्ट्स की अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर सके। उचित मूल्य से अधिक दाम पर चीजों को बेचने पर विक्रेता को सजा हो सकती है।

✯ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का क्या मकसद है?

खाने पीने की चीजें दवा इंधन जैसे पेट्रोलियम के उत्पाद जिंदगी के लिए कुछ अहम चीजें हैं, अगर कालाबाजारी या जमाखोरी की वजह से इन चीजों की आपूर्ति प्रभावित होती है तो आम जनजीवन प्रभावित होगा। साफ शब्दों में कहा जाए तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिस के बगैर इंसान का ज्यादा दिनों तक जिंदा रहना मुश्किल है या इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसी चीजों को आवश्य क वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु की सूची में रखा गया है। इसका एक ही मकसद होता है कि लोगों को जरूरी चीजें उचित दाम पर और आसानी से उपलब्ध हो सके।

सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में रोजगार का सुनहरा अवसर

केवल सच सामाजिक संस्थान और श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट अपने भविष्य के आगामी योजनाओं में सामाजिक एवं बौद्धिक सुधार के क्षेत्र में पुर्नजागरण के शंखनाद हेतु बिहार और झारखण्ड राज्य के मेधावी/सक्षम/योग्य/दक्ष एवं कर्मठ नवयुवकों को अपने टीम में वैतनिक/अवैतनिक रूप से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करना चाहती है। उक्त स्वयंसेवी संस्थान मुख्य रूप से 'अपना घर' (वृद्धाश्रम आवास योजना), परिवार परामर्श केन्द्र, शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम (मूल रूप से निर्धन/बेसहारा लड़कियों हेतु) और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहती है। इन कार्यक्रमों से जुड़कर नवयुवक सामाजिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। उक्त संगठन इसके लिए टीम वर्क के तहत कार्य करना चाहती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समन्वयक के अधीन वार्ड/ पंचायत/ प्रखण्ड/ अनुमण्डल/जिला समन्वयकों की नियुक्ति भी करना चाहती है। इस संस्थान से जुड़कर इच्छुक नवयुवक उक्त पदों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

संस्थान

shruti कम्युनिकेशन ट्रस्ट

www.shruticommunicationtrust.org

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत संचालित

निबंधन संख्या : 22333/2008, आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2549-52 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1073

केवल सच सामाजिक संस्थान

भारतीय सोसायटी एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधित

निबंधन संख्या : 1141 (2009-10), आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

www.ks3.org.in

Regd. Office:- East Ashok Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar)
Jharkhand State Office:- **Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi**
Mob.- 9431073769

Hotel Maurya – Patna is a pioneer project of **Bihar Hotels Limited (BHL).** It is the only **Five Star** category hotel in the State of Bihar with friendly face of affordable luxury. BHL has been successfully operating its Five Star Hotel in Patna since **1978.** Situated in the heart of the city, Patna, the hotel reflects the **historic grandeur** of this city.

Corporate Facilities & Services: Centrally located in the Commercial heart of Patna the Hotel provides Intricately & elegantly designed rooms, Central Air- Conditioning, Direct dialing from rooms with call detail print-out facility, Satellite LED television, Choice of **Seven Convention Halls** of varied capacities, **Heritage rooms** for private dining , **Business Centre, Shopping Arcade, Bank facility, Travel counter, Swimming pool, Safe deposit lockers, Fitness centre & Wi-fi**, all within the hotel premises.

Dining:

- *Vaishali Café* - Walk-in for Breakfast and Business Buffet Lunches. The a-la-carte table offers a multi cuisine and buffet spreads to tinkle those taste buds.
- *Spice Court* – Restaurant serving Indian, Continental, Thai & Chinese cuisine.
- *The Pastry Shop* – Provides all kinds of Baker's confectionery viz; Mouthwatering cakes, Crossiants, Breads, Muffins etc. It also provides free home delivery of cakes of 6 pound onwards.
- *Bollywood Treats*- A matchless meeting point for Munchies, Music, TV shows, Pool Table, Games for kids. Thus, providing Masti not only for adults but also for kids.

Rooms:

- Step into an universe of old world nobility & colonial charm at the spacious VVIP suite of rooms, where your every demand for luxury is met in a manner that's perfected to please. What's more, it's accommodating enough to entertain an entourage of guests. Elegantly designed premium rooms with beautiful interiors and excellent facilities

Total Rooms: 77 – Double: 73, Suites: 04
Credit Cards: Visa, Master, Amex, Bob Cards
Access (in kms): Apt: (07), Rly. Stn.:(01)